www.shabdawanisamachar.page | राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र | RNI NO. DELHI/2003/09049

दैनिक

शब्दवाणी समाचार

नई सोच, नई उम्मीद, बेहतर भविष्य, बेहतर भारत

वर्षः 24 अंकः 261 नई दिल्ली, गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 पृष्ठः संख्या 12 मूल्यः 10 रुपये

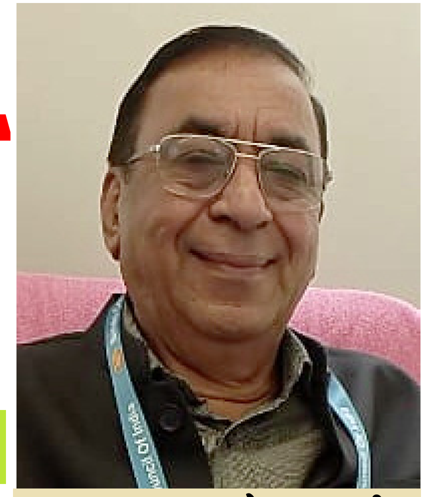

सलाहकार संपादकः अशोक लालवानी

Dedicated to Sindhi Council of India

सार संक्षेप

कांग्रेस ने आर्थिक नाकामी पर मोदी से मांगा जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उसकी जनविरोधी नीतियों के कारण देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और श्री मोदी को 12 वर्ष के शासन के बाद इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि पार्टी पिछले कई महीनों से सरकार को अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के प्रति आगाह करती रही है लेकिन सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

स्टेटहुड पाने को नेकां का दिल्ली चलो 20 जुलाई को

जम्मू। जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) ने अपने सभी विधानसभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) को 19 जुलाई तक नई दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया है ताकि वे 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पार्टी द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग ले सकें, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाना है। पार्टी के निर्देशों के अनुसार, सभी विधायकों को नेतृत्व से औपचारिक अनुमति या किसी अन्य सूचना की प्रतीक्षा किए बिना राष्ट्रीय राजधानी में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे

वॉशिंगटन। भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आठ महीने के अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए हैं। वे रूस के सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने के बाद सुरक्षित रूप से आईएसएस पहुंचे, जहां वे वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रयोगों में हिस्सा लेंगे। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपण के बाद करीब तीन घंटे और दो ऑर्बिट की यात्रा पूरी कर सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान आईएसएस के प्रिचल मॉड्यूल से जुड़ा।

अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, कई घंटे चली कार्रवाई

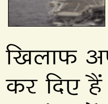

वाशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने बताया कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास और तटीय क्षेत्रों में दर्जनों ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सात घंटे तक हमले किए। सेंटकॉम ने अपने एक बयान में कहा कि यह ऑपरेशन रात 10 बजे (अमेरिकी समयानुसार) खत्म हुआ।

कैबिनेट : चिप उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी

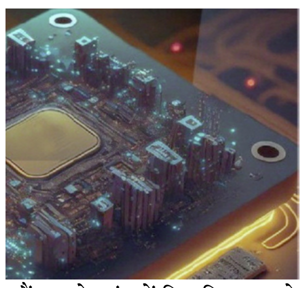

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है और इसके लिए कुल बजट 1.27 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में अश्वनी वैष्णव ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को सतत और दीर्घकालिक समर्थन की आवश्यकता को पहचानते हुए और सेमीकॉन 1.0 के तहत आई गति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य देश को विश्व के सेमीकंडक्टर मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाना है। सेमिकॉन 2.0 के तहत भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए छह प्रमुख स्तंभ तय किए गए हैं। पहले स्तंभ में चिप डिजाइन को बढ़ावा देकर भारतीय कंपनियों को नई तकनीक और बौद्धिक संपदा (आईपी) विकसित करने में सहायता दी जाएगी। दूसरे स्तंभ के तहत चिप बनाने में काम आने वाली मशीनों, रसायनों, गैसों और अन्य सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरे स्तंभ में देश में अधिक सेमीकंडक्टर फैब (चिप निर्माण संयंत्र) स्थापित करने पर जोर होगा। चौथे स्तंभ के अंतर्गत चिप पैकेजिंग और परीक्षण (एटीएमपी/ओसैट) उद्योग को मजबूत किया जाएगा। पांचवें स्तंभ में देश-विदेश के प्रमुख संस्थानों के सहयोग से उन्नत चिप तकनीकों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। छठे स्तंभ के तहत विश्वविद्यालयों और उद्योगों के सहयोग से छात्रों और इंजीनियरों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर कुशल मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि अब तक 12 विनिर्माण इकाइयों को 1.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक के संचयी निवेश के साथ मंजूरी दी गई है। स्वीकृत 12 प्रस्तावों में से तीन कंपनियों, माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है और एक अन्य कंपनी के 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। स्टार्टअप और एमएसएमई से चौबीस (24) सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है, जबकि 105 स्टार्ट-अप/एमएसएमई को उद्योग-मानक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन स्वचालन (ईडीए) उपकरणों तक पहुंच प्रदान की गई है।

मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी, निर्माण के साथ सोर्सिंग और अनुसंधान को मिलेगा प्रोत्साहन

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने 625 अरब रुपये के बजट परिव्यय के साथ मोबाइल फोन निर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष की अवधि (वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) के लिए योजना को मंजूरी दी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत देश में मोबाइल फोन निर्माण पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही घरेलू सोर्सिंग से जुड़ा 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी होगा। वहीं, भारतीय ब्रांड बनाने के लिए डिजाइन और अनुसंधान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

वैष्णव ने बताया कि योजना अवधि के दौरान मोबाइल फोन उत्पादन 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही इस योजना से लगभग 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा और आर्थिक विकास में योगदान भी मिलेगा।

सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य तकनीकी संप्रभुता हासिल करने, व्यापक आर्थिक मूल्य प्राप्त करने और डिजाइन एवं अनुसंधान एवं विकास में भारतीय पेटेंट बनाने के लिए भारतीय ब्रांडों का निर्माण करना भी है।

छात्रों की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्र निराश

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की डिजिटल कॉपी जांच की व्यवस्था (ओएसएम) को लेकर हो रही छात्रों की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिस्टम में छात्रों को लगातार दिक्कत आ रही है। छात्रों में काफी निराशा और हताशा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मामले को विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए। कोर्ट चाहता है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार कॉपी जांच की खामियों को गंभीरता से ले रही है। इसके लिए एस. राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।

छात्रों की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है

पारदर्शी और स्पष्ट नियम बनाए जाने की मांग

राकेश बिंजोला की ओर से दायर याचिका में सीबीएसई की कॉपी जांच के लिए पारदर्शी और स्पष्ट नियम बनाए जाने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि इन नियमों की निगरानी के लिए एक हाई-पावर कमेटी बनाई जाए। जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रवेश परीक्षा पास कर ली है या प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, उन्हें बोर्ड के न्यूनतम अंकों की शर्त से छूट मिलनी चाहिए।

भारत-ब्रिटेन सीईटीए लागू होने से व्यापारिक संबंधों को मिलेगी नई गति : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) तथा सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे तथा किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत-ब्रिटेन साझेदारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) और सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाएं ठोस अवसरों में परिवर्तित होंगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सीईटीए भारतीय किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगा। इससे कई प्रमुख भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन के बाजार तक अधिक सशक्त पहुंच मिलेगी। साथ ही प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा तथा कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों को महत्वपूर्ण राहत देगा और भारतीय उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच आपसी विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार आधारित भविष्य की साझेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लक्ष्य के साथ आगे भी मिलकर कार्य करते रहेंगे।

2028 तक यमुना में एक बूंद गंदा पानी नहीं जाएगा: अमित शाह

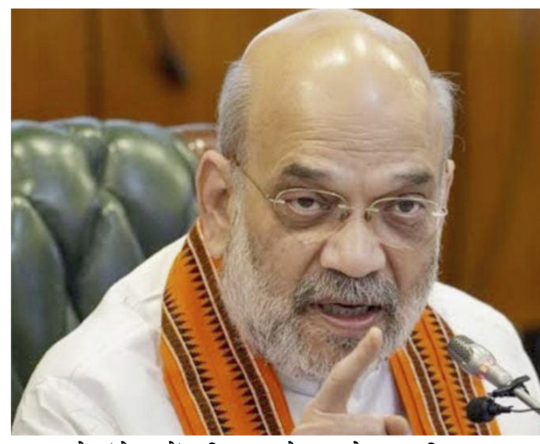

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच दिल्ली में गोबर के वैज्ञानिक निस्तारण और कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक यह सुनिश्चित करना है कि यमुना नदी में एक भी लीटर गंदा पानी न जाए।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सहकारिता सचिव तथा केंद्र और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि यह समझौता देश के सभी बड़े शहरों के लिए स्वच्छता का एक आदर्श मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से पशुपालकों की आय बढ़ेगी, शहरी स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, कंप्रेस्ड बायो-गैस का उत्पादन होगा और जैविक खेती को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक यमुना को स्वच्छ देखना चाहता है लेकिन यमुना में गिरने वाले प्रदूषण को रोके बिना यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यमुना शुद्धिकरण के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री ने बताया कि दिल्ली में सीवर के पानी और औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन के लिए लगभग 80 ट्रीटमेंट प्लांटों पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है कि भविष्य में गोबर का एक छोटा हिस्सा भी यमुना में न पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग सवा लाख मवेशियों से निकलने वाले अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के बिना यमुना को स्वच्छ बनाना संभव नहीं है।

शाह ने कहा कि नंगली, घोघा-गोयला और गाजीपुर में स्थापित किए जाने वाले अपशिष्ट निस्तारण संयंत्रों के माध्यम से गोबर का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल दिल्ली बल्कि देश के सभी महानगरों के लिए अनुकरणीय मॉडल बनेगी और भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के करोड़ों पशुपालकों को भी इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत गोबर उपलब्ध कराने पर पशुपालकों को प्रति किलोग्राम एक रुपये का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

भागलपुर में एआई एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की होगी स्थापना : सम्राट

211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन कार्य का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को भागलपुर के गोराडीह में नवस्थापित डिग्री कॉलेज, कासिल परिसर से राज्यभर के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुये सीएम ने कहा कि आज का दिन बिहार के लिए गौरव का दिन है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे प्रत्येक प्रखंड के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

सीएम सम्राट ने कहा कि बिहार की गौरवशाली शैक्षणिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आधुनिक स्वरूप में पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 220 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है तथा अगले एक वर्ष के भीतर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही बिहार में चार नए निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बिहार की समृद्धि का सबसे बड़ा आधार बनेगी और राज्य को ज्ञान एवं नवाचार का केंद्र बनाएगी।

सीएम ने आगे कहा कि क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु को 30 नवंबर तक हर हाल में पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर में लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यहां उद्योग स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने बिहार से बाहर रह रहे लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने राज्य लौटें और बिहार की समृद्धि एवं विकास में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा चुकी है तथा शेष पात्र महिलाओं के खातों में 25 जुलाई को राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना और पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुंगेर से भागलपुर तक 83 किलोमीटर लंबी गंगा मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो पूरा होने के बाद बिहार का प्रमुख आकर्षण बनेगा। सबौर से राजमहल बॉर्डर तक इसका विस्तार किया जायेगा। बाहर से भी लोग इसे देखने आयेंगे। कहलगांव के समीप गंगा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बटेश्वर धाम मंदिर तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोप-वे का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर क्षेत्र में दो एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जिनमें सुल्तानगंज में प्रस्तावित एयरपोर्ट भी शामिल है। इससे क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पॉवर प्लांट लगने जा रहा है। इसकी क्षमता को 1600 मेगावाट और बढ़ाया जायेगा। इस परियोजना में 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर के अन्तर्गत अब तक करीब 6 लाख आवेदन आये हैं जिनमें से साढ़े पांच लाख आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। अब तक सिर्फ 4 अधिकारियों एवं कर्मियों को तीसरा नोटिस देने की नौबत आयी है। इसका मतलब हुआ कि अधिकारी एवं कर्मी जनता की शिकायतों का निष्पादन ससमय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व गोराडीह में नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय के पठन-पाठन कार्य का शिलापट अनावरण कर शुभारंभ किया।

भारत-यूके व्यापार समझौता हुआ लागू

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) बुधवार से लागू हो गया है। इससे देश में कपड़ा, चमड़े, आभूषण एवं रत्न, समुद्री उत्पादों, केमिकल और अन्य क्षेत्रों से जुड़े निर्यातकों के लिए यूके का बाजार खुला गया और उन्हें अब पहले के मुकाबले निर्यात के अधिक अवसर मिलेंगे। भारत-यूके सीईटीए के लागू होने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ यह समझौता, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है। इससे देश के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को यूके में जीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जो कि भारत की 100 प्रतिशत ट्रेड वैल्यू को कवर करता है।

कई क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए बढ़ेंगे अवसर

मदन मित्रा ने भी छोड़ा ममता का साथ, पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा

कोलकाता, 15 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। राज्य के पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के कामारहाटी से तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इसके बाद वे सीधे पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे और वहां विपक्ष के नेता ऋतब्रत बंद्योपाध्याय के कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की।

बुधवार सुबह मदन मित्रा अपने घर से स्वयं कार चलाकर विधानसभा पहुंचे। विपक्ष के नेता के कक्ष में पहुंचने के बाद में उन्होंने मीडिया के सामने भावुक अंदाज में कहा कि जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें सही और गलत का फैसला करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि वे अभी भी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और बंगाल की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन पार्टी में जो भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां उनके पास थीं, उन सभी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भविष्य में जब बंगाल के इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तब यह भी दर्ज होगा कि एक व्यक्ति की वजह से 213 सीटें जीतने वाली पार्टी का राजनीतिक नुकसान हुआ।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नए सत्र का दीक्षारंभ, 110 विद्यार्थियों का पारंपरिक स्वागत

नई दिल्ली, 15 जुलाई (दिव्य भारत ब्यूरो)। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाजों के साथ आयोजित दीक्षारंभ समारोह के माध्यम से हुआ। अभिमंच सभागार में आयोजित इस समारोह में नई दिल्ली परिसर तथा चार क्षेत्रीय केंद्रों के नवप्रवेशित विद्यार्थियों का भव्य स्वागत किया गया। समारोह में नई दिल्ली केंद्र और एनएसडी के बेंगलुरु, गंगटोक (सिक्किम), वाराणसी और अगरतला (त्रिपुरा) स्थित क्षेत्रीय केंद्रों के करीब 110 नवप्रवेशित विद्यार्थियों ने भाग लिया। नई दिल्ली केंद्र में विद्यार्थियों को नाट्य कला में तीन वर्षीय डिप्लोमा, गंगटोक केंद्र में एक वर्षीय नाट्य कला प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, बेंगलुरु केंद्र में अभिनय का एक वर्षीय पाठ्यक्रम, वाराणसी केंद्र में भारतीय शास्त्रीय रंगमंच तथा अगरतला केंद्र में थिएटर-इन-एजुकेशन (टीआईई) के अंतर्गत एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समारोह में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सोसायटी के उपाध्यक्ष प्रो. भरत गुप्त, एनएसडी के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी, कुलसचिव प्रदीप कुमार मोहंती, प्रो. शंतनु बोस, राजेश सिंह, यशराज जाधव, अरुण कुमार मलिक, विवेक एम्मानेनी तथा पुस्तकालयाध्यक्ष एवं जनसंपर्क अधिकारी (प्रभारी) डॉ. ई. गजलक्ष्मी सहित कई वरिष्ठ शिक्षकों एवं अधिकारियों ने भाग लिया। चारों क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशकों वीणा शर्मा भूसनूरमठ (बेंगलुरु), सौति चक्रवर्ती (गंगटोक), विवेक एम्मानेनी (वाराणसी) और बिप्लब बोरकाकोटी (अगरतला) ने भी समारोह में उपस्थित होकर विद्यार्थियों का स्वागत किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय परंपरा के अनुरूप मंगलाचरण एवं वैदिक विधि-विधानों के साथ हुआ। इसके बाद श्री वेत्री भूपति और उनकी टीम ने शास्त्रीय संगीत की मनमोहक प्रस्तुति देकर समारोह को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। दीक्षारंभ समारोह के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का प्रेरणादायी शुभारंभ हुआ।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को हर हफ्ते दो ई-मुलाकात की दी इजाजत

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद को हर हफ्ते दो ई-मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को छह साल से हर हफ्ते दो ई-मुलाकात करने की अनुमति दी गई थी और इस दौरान उसने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को छह साल से हफ्ते में दो ई-मुलाकात की सुविधा मिल रही थी, लेकिन एक मई से ये संख्या घटाकर एक कर दी गई, जबकि उसने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने उमर खालिद की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक उमर खालिद को हफ्ते में एक बार ही ई-मुलाकात की सुविधा दी जा सकती है। इस मामले में 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द की जनकपुरी स्कूल दुष्कर्म केस में महिला टीचर की जमानत

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनकपुरी में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित महिला टीचर को मिली जमानत को निरस्त कर दी है। न्यायाधीश सौरभ बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने महिला टीचर को तीन दिनों में सरेंडर करने का आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट ने महिला टीचर को 20 मई को जमानत दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपित को जमानत देकर गलती की है। उन्होंने कहा ये मामला पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का है, जिसमें कम से कम बीस साल की जेल का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस ने आरोपित महिला टीचर को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग की थी। इस मामले में पीड़ित बच्ची ने आरोपित की पहचान की है और इस घटना के बारे में बयान दिया है। टीचर पर आरोप है कि उसने प्रशासन से इस घटना की जानकारी छिपाई। इसके पहले उच्च न्यायालय ने 29 जून को आरोपित स्कूल के केयरटेकर को मिली जमानत को भी निरस्त कर दिया था। ये घटना 30 अप्रैल की है। इस घटना को लेकर बच्ची की मां ने जनकपुरी थाने में एक मई को शिकायत दर्ज कराई थी। दुष्कर्म की घटना बच्ची के स्कूल में दाखिले के दूसरे दिन की ही है। 30 अप्रैल को जब बच्ची स्कूल से लौटी, तो उसने दर्द की शिकायत की। बच्ची की मां ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि आरोपित केयरटेकर उसे स्कूल के सुनसान क्षेत्र में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक बच्ची ने आरोपित की पहचान की, जिसके बाद एक मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट का सोनम वांगचुक के अनशन पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित पेपर लीक और शिक्षा क्षेत्र में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन को रुकवाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 16 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

याचिका वकील राकेश कुमार सैनी ने दायर की है। सुनवाई के दौरान सैनी ने कहा कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता विरोध के अपने अधिकार का उपयोग करते हुए पूरे देश के सामने अपनी जान देने को तैयार है। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर 16 जुलाई को ही सुनवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के वकील को इस मामले पर निर्देश लेकर आने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो याचिका की प्रति केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों को उपलब्ध कराएं।

दिल्ली में तय समय सीमा में मिलेंगी सरकारी सेवाएं, सरकार ने विधेयक को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने नागरिकों के हित में निर्णय लेते हुए दिल्ली (राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस) बिल-2026, दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार) विधेयक- 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधेयक में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था की गई है। बिना उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रति दिन 250 रुपये का दंड, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये होगी, लगाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस विधेयक से नागरिक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त हों। सरकारी विभागों और अधिकारियों को सेवा प्रदान करने में होने वाली देरी तथा लापरवाही के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। यह कानून दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सरल, प्रभावी तथा तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक वर्ष 2011 के दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध सेवा प्रदाय का अधिकार) अधिनियम का स्थान लेगा। नई व्यवस्था में आधुनिक डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाएगा, जिससे सेवाओं का वितरण अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी कर यह निर्धारित करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी। इन सभी सेवाओं, उनकी समय-सीमा और संबंधित नामित अधिकारियों की अधिसूचना दिल्ली सरकार द्वारा जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विधेयक में आवेदन से लेकर सेवा प्राप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट

आवेदन संख्या मिलेगी तथा उसकी स्थिति की वास्तविक समय में ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। आवेदन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी और विभाग भी समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन निगरानी करेंगे। इससे नागरिकों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। साथ ही शासन प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और दक्ष बनेगी तथा सरकारी सेवाओं का वितरण अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वतः अपील (ऑटोमैटिक एस्केलेशन) की व्यवस्था है। यदि कोई नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो नागरिक को अलग से अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मामला स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील के रूप में पहुंच जाएगा। यदि निर्धारित अवधि में वहां भी निर्णय नहीं होता है, तो मामला स्वतः दिल्ली राइट टू सर्विस आयोग के समक्ष पहुंच जाएगा। इससे पूरी व्यवस्था में जवाबदेही स्वतः सुनिश्चित होगी और नागरिकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।

विधेयक के अनुसार प्रत्येक विभाग में नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह प्राधिकारी सेवा में देरी अथवा आवेदन अस्वीकार किए जाने से संबंधित अपीलों पर निर्णय करेंगे, आवश्यकता होने पर सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश देंगे, देरी के लिए जिम्मेदारी तय करेंगे तथा आवश्यक होने पर दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर सकेंगे। सामान्यतः सभी अपीलों का निस्तारण 30 दिनों के भीतर करने का प्रावधान किया गया है।

विधेयक के अंतर्गत एक स्वतंत्र वैधानिक दिल्ली राइट टू सर्विस आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। आयोग द्वितीय अपीलों की सुनवाई करेगा, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करेगा, लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करेगा तथा आवश्यकतानुसार नई सेवाओं को इस कानून के दायरे में शामिल करने की अनुशंसा करेगा। आयोग प्रशासनिक सुधारों के सुझाव देगा, आवश्यक होने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकेगा, कानून के प्रावधानों के अनुरूप अपने निर्णयों की समीक्षा भी कर सकेगा तथा प्रतिवर्ष सेवा वितरण और कानून के क्रियान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

विधेयक में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। बिना उचित कारण के सेवा देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से, अधिकतम 5,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकेगा। इसी प्रकार किसी आवेदन को अनुचित रूप से अस्वीकार किए जाने पर 250 रुपये से 5,000 रुपये तक का एकमुश्त दंड लगाया जा सकेगा। दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के लागू होने से नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं मिलेंगी, अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर कम होंगे, डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के चुनाव संपन्न, भाजपा ने 10 जोन में जीत हासिल की, आआपा को दो जोन में सफलता

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य पदों के लिए बुधवार को हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बढ़त कायम रखते हुए 12 में से 10 जोन के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। वहीं आम आदमी पार्टी (आआपा) को दो जोन में अध्यक्ष पद पर सफलता मिली।

नजफगढ़, शाहदरा दक्षिण, शाहदरा उत्तर, दक्षिण, केशवपुरम, नरेला, सिविल लाइन, सिटी एसपी, सेंट्रल और वेस्ट जोन में भाजपा ने जीत हासिल की। वही रोहिणी, करोल बाग और कुछ उपाध्यक्ष पदों पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली।

चुनाव के परिणामः नजफगढ़ जोन में भाजपा के तीनों उम्मीदवारों ने मारी बाजी।

अध्यक्ष जयवीर सिंह राणा, उपाध्यक्ष सुषमा राठी और स्थायी समिति सदस्य शशि यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए। शाहदरा दक्षिण जोन में भाजपा के यशपाल सिंह 18 मत प्राप्त कर अध्यक्ष चुने गए, जबकि आआपा उम्मीदवार को छह मत मिले। उपाध्यक्ष राजू सचदेवा तथा स्थायी समिति सदस्य मुनेश निर्विरोध निर्वाचित हुए। शाहदरा उत्तर जोन में भाजपा के पंकज लूथरा अध्यक्ष और बृजेश सिंह उपाध्यक्ष चुने गए दोनों को 20-20 मत मिले, जबकि आआपा प्रत्याशियों को 12-12 मत प्राप्त हुए। दक्षिण जोन में भाजपा के धर्मवीर सिंह अध्यक्ष और ममता यादव उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दोनों को 12-12 मत मिले, जबकि आआपा को 10-10 मत प्राप्त हुए। केशवपुरम जोन में भाजपा के विनीत वोहरा, मीनू गोयल और सुशील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए।

रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष पद पर पुष्पा को 12 मत मिले, जबकि भाजपा को 11 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर भी आआपा के रमेश चंद 12 मतों के साथ विजयी रहे। करोल बाग जोन में आआपा के तीनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष अलका ढींगरा, उपाध्यक्ष कविता चौहान और स्थायी समिति सदस्य राजन अरोड़ा निर्विरोध निर्वाचित हुए। नरेला जोन में भाजपा की जनता देवी 13 मतों के साथ अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। उपाध्यक्ष दिनेश कुमार तथा स्थायी समिति सदस्य पवन कुमार निर्विरोध चुने गए। सिविल लाइन जोन में भाजपा के गुलाब सिंह 11 मत प्राप्त कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत सदस्य संजय त्यागी 11

12वीं पास छात्र ने लाइसेंसी रायफल से खुद को गोली मारी, सुसाइड नोट में लिखा- सोशल गिल्ट

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी इलाके में मंगलवार शाम 17 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर लाइसेंसी 12 बोर रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके से पुलिस को एक हस्तलिखित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने 'सोशल गिल्ट' (सामाजिक अपराधबोध) का जिक्र किया है। हालांकि, पुलिस को अब तक की जांच में किसी तरह की साजिश या आपराधिक पहलू के संकेत नहीं मिले हैं।

पुलिस के अनुसार, बुधवार शाम तिलक नगर थाने को चौखंडी स्थित एक मकान में किशोर द्वारा खुद को गोली मारने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और कैट्स एंबुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक किशोर की मौत हो चुकी थी। जांच में पता चला कि 17 वर्षीय नाबालिग अपने परिवार के साथ चौखंडी में किराये के मकान में रहता था। उसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह परिवार में सबसे छोटा था। उसके पिता पिछले करीब 20 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं और द्वारका क्षेत्र में छोले-कुलचे की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय घर में किशोर, उसके पिता और एक रिश्तेदार मौजूद थे। शाम करीब पांच बजे किशोर बाथरूम में गया और वहीं रखी 12 बोर की लाइसेंसी रायफल से खुद को गोली मार ली। यह रायफल पहले उसके दादा के नाम पर लाइसेंसशुदा थी, जो सुरक्षा गार्ड थे। बाद में हथियार का लाइसेंस उसके पिता के नाम स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि हथियार का लाइसेंस वर्ष 2030 तक वैध है। घटना की सूचना पर क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। मौके से एक हस्तलिखित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्र ने सोशल गिल्ट का उल्लेख किया है। पुलिस फिलहाल नोट की लिखावट और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है, फिर भी सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

ऑपरेशन चक्र में द्वारका पुलिस का बड़ा एक्शन, 72 घंटे में 30 ऑटो लिफ्टर दबोचे, 64 चोरी के वाहन बरामद

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए द्वारका जिला पुलिस ने 72 घंटे का विशेष अभियान ऑपरेशन चक्र चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 30 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार कर 64 चोरी के वाहन बरामद किए। बरामद वाहनों में 61 दोपहिया और तीन चारपहिया वाहन शामिल हैं। इन बरामदगी के साथ वाहन चोरी के 64 मामलों का भी खुलासा हुआ है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य वाहन चोर गिरोहों, चोरी के वाहन खरीदने-बेचने वाले नेटवर्क और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसना था। अभियान में जिले के सभी थाना पुलिस के अलावा एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (एएटीएस) ने प्रमुख भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों के

अनुसार, अभियान के दौरान खुफिया सूचना के आधार पर कई स्थानों पर छापेमारी की गई। इसके अलावा ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) सिस्टम की मदद से संदिग्ध वाहनों की निगरानी की गई और जिलेभर में व्यापक स्तर पर पिकेट चेकिंग अभियान चलाया गया। संवेदनशील पार्किंग स्थलों पर भी विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए 30 आरोपितों में 17 ऐसे अपराधी हैं, जो पहले भी वाहन चोरी सहित विभिन्न मामलों में शामिल रह चुके हैं।

दिल्ली कैबिनेटः तय समय सीमा में मिलेंगी सरकारी सेवाएं, विधयेक को मंजूरी

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली वालों को तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली (नागरिकों का तय समय-सीमा में और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। यह विधेयक 2011 के कानून की जगह लेगा और नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस के लिए एक आधुनिक, टेक्नोलॉजी-आधारित कानूनी ढांचा तैयार करेगा। यह जानकारी सीएमओ दिल्ली सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। दिल्ली सरकार के मुताबिक नागरिकों को अब तय समय-सीमा में सेवाओं का कानूनी अधिकार मिल गया है। नागरिकों को शुरू से आखिर तक डिजिटल सेवा मिलेगी। देरी वाले मामलों का अपने-आप आगे बढ़ना तय होगा। नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्वतंत्र व्यवस्था होगी।

दिल्ली में 28 रूटों पर चलेंगी महिला स्पेशल 56 इलेक्ट्रिक बसें

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) राष्ट्रीय राजधानी के 28 रूटों पर महिलाओं के लिए स्पेशल 56 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगी। इनमें दिल्ली के 15 प्रमुख व्यस्त रूट पर 30 महिला स्पेशल बस सेवाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ एवं साउथ कैंपस समेत दूसरे बड़े शिक्षण संस्थानों और प्रमुख रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली 13 समर्पित रूटों पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल (यू-एसपीएल) बस सेवाएं शामिल हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना और रेगुलर बस सेवाओं में भीड़भाड़ को कम करना है। इन रूटों की पहचान उन कॉरिडोर के आधार पर किया गया है, जहां महिला यात्रियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है। परिवहन मंत्री ने बताया कि 30 लेडीज स्पेशल बसें ऑफिस के व्यस्त समय (पीक आवर्स) के दौरान दोनों दिशाओं में चलेंगी। सुबह की सेवाएं प्रातः 7 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह के 9 बजे के बीच चलेंगी और वापसी की सेवाएं शाम को 4 बजकर 32 मिनट से लेकर 6 बजकर 15 मिनट के बीच संचालित होंगी। ये बसें राजधानी दिल्ली के प्रमुख रोजगार केंद्रों, कमर्शियल इलाकों, इंस्टीट्यूशनल हब और प्रमुख मेट्रो इंटरचेंज स्टेशनों को जोड़ेंगी, जिससे कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा संभव हो सकेगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सर्विस को कॉलेज को शेड्यूल के हिसाब से प्लान किया गया है। ये बस सर्विस नजफगढ़, रोहिणी, जनकपुरी, मुंडका, मयूर विहार, कालकाजी, पल्ला और धौलाकुआं जैसे बड़े रिहायशी इलाकों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत कई प्रमुख कॉलेजों से सीधे जोड़ेंगी।

एमसीडी के 10 जोन में भाजपा अध्यक्ष बनने से विकास को मिली नई गति : हर्ष मल्होत्रा

नई दिल्ली, 15 जुलाई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम की वार्ड समिति (जोन) चुनाव के नतीजे दिल्ली के विकास के लिए ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि निगम पार्षदों ने 12 में से 10 जोन में भाजपा के अध्यक्ष चुनकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विकास एजेंडे पर विश्वास जताया है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि शहरी सदर क्षेत्र के पार्षदों ने भाजपा का क्षेत्रीय अध्यक्ष चुनकर पुरानी दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विकास यात्रा से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि पुरानी दिल्ली के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि करीब 24 वर्ष बाद शहरी सदर क्षेत्र में भाजपा की उषा शर्मा क्षेत्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। यह पुरानी दिल्ली के लिए एक नया इतिहास है। उन्होंने सभी पार्षदों और क्षेत्र के व्यापारियों तथा नागरिकों को विश्वास दिलाया कि भाजपा उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरेगी और पुरानी दिल्ली के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

भविष्यफल

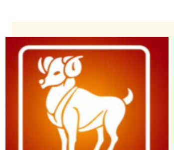

मेष- यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। कामकाज में आ रही बाधा को दूर कर लेंगे। सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बन जाएगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम पर पैनी नजर रखिए। यात्रा आवश्यक होगी। शुभांक-5-7-9

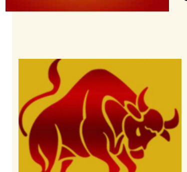

वृष- लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। पर प्रपंच में ना पड़कर काम पर ध्यान दीजिए। इच्छित कार्य सफल होंगे। शुभांक-6-8-9

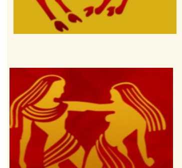

मिथुन- दुर्लभ स्वप्न साकार होंगे। आलस्य का त्याग करें। पुरुषार्थ का सहारा लें। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा। शुभांक-7-8-9

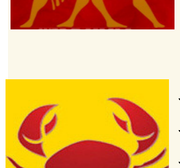

कर्क- विवाद समाप्त होंगे। शुभ संदेशों से मन खिला-खिला रहेगा। परेशानीयां स्वतः ही दूर होती प्रतीत होगी। अध्ययन में रुचि पैदा होगी। अभिभावकों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने होंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। स्त्री, संतान, मित्र के साथ मनोविनोद बढ़ेगे। शुभांक-4-6-9

सिंह- नौकरी में सावधानीपूर्वक कार्य करें। शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। शुभांक-4-6-8

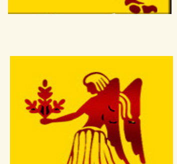

कन्या- अपने अधीनस्थ लोगों से कम सहयोग मिलेगा। आवेश में आना आपके हित में नही होगा इसलिए व्यवहार व वाणी पर नियत्रंण रखें। पारिवारिक परेशानी बढ़ेगी। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। बाहरी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। विपरीत परिस्थितियों में भी हानि नहीं होगी। शुभांक-3-6-9

तुला- व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। आलस्य का त्याग करें। कार्यसिद्धि होने में देर नहीं लगेगी। आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर वार्ता होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। स्त्री-संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। शुभांक-5-7-8

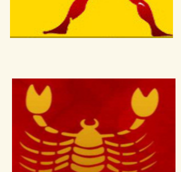

वृश्चिक- समय पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। पुराने मित्र से मिलन होगा। स्वविवेक से कार्य करें। शुभांक-3-5-7

धनु- पुरानी गलती का पश्चाताप होगा। मेहमानों का आगमन होगा। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। शुभांक-3-6-7

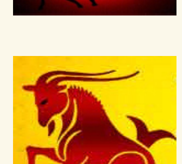

मकर- जीवनसाथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। बचते-बचते कलह विवाद का डर रहेगा। हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात दूर हो जाएगी। अपने काम आसानी से बनते चले जाएंग। साथ ही आगे के लिए रास्ता भी बन जाएगा। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। शुभांक-3-5-7

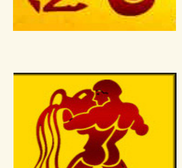

कुंभ- कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। नवीन उद्योगों के अवसर बढ़ेंगे व अभिलाषाएं पूर्ण होगी। कुछ भ्रामक धारणाओं का खंडन होगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। शुभांक-2-4-6

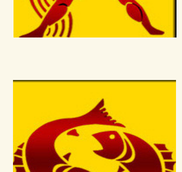

मीन- अपनी गतिविधियों पर पुनर्विचार करें। वैचारिक द्वन्द्व और असंतोष बना रहेगा। किसी सूचना से पूर्ण निर्णय सम्भव। सुख आरोग्य प्रभावित होगा। शत्रुभय, चिंता, संतान को कष्ट, अपव्यय के कारण बनेंगे। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। आवेग में आकर किये गए कार्यों का म्लान रहेगा। शुभांक-3-5-7

पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आज से

यात्रा में जुटेंगे 10 लाख श्रद्धालु : होटल छह महीने पहले ही फुल, 1500 का कमरा 50 हजार तक पहुंचा

● पुरी / (एजेंसी)

ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा गुरुवार, 16 जुलाई से शुरू होगी। नौ दिन तक चलने वाला यह उत्सव 24 जुलाई को संपन्न होगा। इस बार रथयात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। भारी भीड़ को देखते हुए शहर के होटल और लॉज करीब छह महीने पहले ही बुक हो चुके हैं। जिला प्रशासन के अनुसार, इस वर्ष होटल बुकिंग फरवरी से ही शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर और रथयात्रा मार्ग के आसपास स्थित होटलों की सबसे अधिक मांग रही। खासकर वे कमरे, जिनकी बालकनी या खिडक़ी से रथयात्रा का सीधा दृश्य दिखता है, उनकी बुकिंग सबसे पहले हुई।

बढ़ती मांग के कारण होटल किराए में भी भारी उछाल आया है। सामान्य दिनों में 1500 से 2000 रुपए प्रतिदिन किराए वाले कमरे रथयात्रा के दौरान तीन दिन के लिए 50 हजार रुपए तक में बुक किए जा रहे हैं। पुरी में करीब 1200 होटल और लॉज हैं।

हावड़ा की अनोखी रथयात्रा, गोद में विराजते हैं भगवान जगन्नाथः पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हर साल एक अनूठी रथयात्रा भी निकाली जाती है। यहां पारंपरिक रथ नहीं बनाया जाता और न ही रस्सियों से रथ खींचा जाता है।

इसके बजाय कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज के बांग्ला विभाग के प्रोफेसर डॉ. शेख मकबूल इस्लाम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के विग्रह को अपनी गोद में लेकर करीब 400 मीटर की परिक्रमा करते हैं।

इस आयोजन में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग समान रूप से भाग लेते हैं। डॉ. इस्लाम 1992 से भगवान जगन्नाथ पर शोध कर रहे हैं और इस विषय पर 14 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। वर्ष 1996 में उन्होंने अपने घर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित की थी। वहीं, 2009 से वे हर वर्ष रथयात्रा के अवसर पर इस विशेष परिक्रमा का आयोजन कर रहे हैं।

शरीर ही रथ है

डॉ. शेख मकबूल इस्लाम बताते हैं कि उनकी यह परंपरा कठोपनिषद् के श्लोक *''आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु''* से प्रेरित है। उनके अनुसार, जब शास्त्र शरीर को ही रथ बताते हैं तो अलग रथ की आवश्यकता नहीं रह जाती। वे पूरी तरह शाकाहारी हैं और पुरी की परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ को 35 प्रकार के सात्विक व्यंजन बनाकर विधि-विधान से भोग अर्पित करते हैं।

भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री मेनन नासा मिशन पर आईएसएस पहुंचे

● मास्को/ (एजेंसी)

नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और रूस के दो कॉस्मोनॉट सोयुज एमएस-29 अंतरिक्ष यान से बुधवार तड़के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। वो तीन घंटे की यात्रा के बाद यहां पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका गले मिलकर और हाथ हिलाकर स्वागत किया गया। मेनन और रूसी कॉस्मोनॉट प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना को लेकर रोस्कोस्मोस का अंतरिक्ष यान मंगलवार रात 8:17 बजे भारतीय समय के मुताबिक बैकोनूर से रवाना हुआ। उस समय आईएसएस कॉस्मोड्रोम के ऊपर से गुजर रहा था। 8 मिनट में शुरुआती कक्षा में पहुंचने के बाद सोयुज एमएस-29 ने अंतरिक्ष यान रात 11:52 बजे स्टेशन से जुड़ा के प्रिचल मॉड्यूल से जुड़ गया।

अंतरिक्ष यान रात 11 :52 बजे स्टेशन से जुड़ा

ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया

अमेरिका ने ईरान पर 7 घंटे तक बरसाए बम, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

हमले में ईरान के 35 लोगों की मौत, 300 घायल

● तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन / (हि.स.)

यूएस-ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर सैन्य कार्रवाई की। करीब 7 घंटे चले ऑपरेशन में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और तटीय रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। हमले में ईरान में 35 लोगों की मौत हुई 300 लोग घायल हो गए। 72 लोग अस्पताल में भर्ती है। वहीं, आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने बहरीन के यूएस फिफ्थ फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया।

ट्रम्प की चेतावनी- अगले हमले और बड़े होंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान बातचीत के लिए आगे नहीं आता है तो अमेरिका अगले सप्ताह उसके बिजलीघरों और पुलों को भी निशाना बना सकता है। दूसरी ओर, ईरान ने साफ किया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपनी रणनीति जारी रखेगा।

कतर पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची बुधवार को अचानक कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। वह कतर के पूर्व अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। अराघची का यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब हाल में ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे। इससे पहले कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अराघची अपने दौरे के दौरान संघर्ष विराम बहाल करने को लेकर कोई चर्चा करेंगे या नहीं।

ओमान तट के नज़दीक जहाज़ पर हुए हमले में भारतीय क्रू सदस्य की मौत की पुष्टि: दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बुधवार को पुष्टि की है कि ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज जीएएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले के बाद लापता हुए एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। 30 साल के हरांब कर्माकर साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज जीएफएस गैलेक्सी में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत थे।

ग्रामोदय विश्वविद्यालय में निकली नशा मुक्ति जागरूकता रैली

चित्रकूट, 15 जुलाई (दिव्य भारत ब्यूरो)। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के तत्वावधान में नशा मुक्ति के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में भव्य नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।

रैली का शुभारंभ कला संकाय के शिक्षा विभाग परिसर से डॉ. श्याम सिंह गौर ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता का संदेश दिया।

प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां एवं बैनर लेकर नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, नशामुक्त हो हर इंसान, स्वस्थ समाज की पहली पहचान तथा नशा मुक्त भारत, सशक्त भारत जैसे प्रेरक नारों के माध्यम से समाज को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नशा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके परिवार और समाज पर भी गंभीर दुष्प्रभाव डालता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, योग तथा सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी से ही नशामुक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। रैली का समापन नशामुक्त जीवन अपनाने तथा समाज में नशा उन्मूलन के प्रति व्यापक जन-जागरूकता फैलाने की शपथ के साथ हुआ।

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक मानसून सत्र में होंगे पारित : एकनाथ शिंदे

नई दिल्ली (दिव्य भारत ब्यूरो)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया है कि महिला

आरक्षण और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पारित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के साथ जनप्रतिनिधित्व को संतुलित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में शिंदे ने कहा कि कई लोकसभा क्षेत्रों की आबादी 20 से 25 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे जनप्रतिनिधियों के लिए विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन से सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व और विकास के बेहतर अवसर मिलेंगे। महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए शिंदे ने कहा कि वर्षों तक यह केवल चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाने का साहस दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले संसद सत्र में विपक्ष के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से महिला हित में इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें सिंचाई योजनाएं, मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना, रेलवे, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगर विकास और ग्राम विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने इन प्रस्तावों पर आगामी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विचार का आश्वासन दिया है। साथ ही संबंधित सांसदों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे को सौंपी गई है। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के साथ आए दो-तिहाई बहुमत वाले सांसदों से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और मामला लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाएगा।

प्रेस वार्ता में शिंदे ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 32 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने तथा महाराष्ट्र को यूपीए शासन की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नेशन फर्स्ट की भावना से कार्य कर रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर बिना किसी दल का नाम लिए शिंदे ने कहा कि जो लोग पहले राम भक्तों का विरोध करते थे, वे आज रामरक्षा का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता विकास और हिंदुत्व की राजनीति के साथ खड़ी है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्जमाफी का वादा पूरा किया है और बजट में किसानों को राहत देने के कई फैसले लिए गए हैं।

राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति को मिली मंजूरी, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत

नई दिल्ली (एस एन वर्मा/दिव्य भारत)। यूरिया उत्पादन में भारत के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज उर्वरक विभाग के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 को मंजूरी दे दी है।

यह नीति भारत में नए गैस-आधारित यूरिया उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे पहले साल 2012 में बनाई गई निवेश नीति अक्टूबर 2019 में समाप्त हो गई थी ,2012 की निवेश नीति के तहत, देश में छह नए यूरिया इकाइयों की स्थापना हुई थी। जिनमें से चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों और दो निजी संस्थाओं की तरफ से लगाए गए थे।

वर्तमान में भारत में 33 यूरिया उत्पादन इकाइयां चल रही हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन है। इसके बावजूद, देश की कुल यूरिया मांग और घरेलू उत्पादन क्षमता के बीच अंतर बना हुआ है, जिसे फिलहाल आयात के जरिए पूरा किया जाता है। उर्वरक विभाग को नए संयंत्रों के लिए कई प्रस्ताव पहले ही मिल चुके हैं, ऐसे में यह निवेश नीति स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक ढांचा तैयार करेगी।

निवेश के माहौल को अधिक आकर्षक और टिकाऊ बनाने के लिए नई नीति में 2012 के ढांचे के मुकाबले कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं,,बेहतर पारदर्शिता के लिए नीति में संयंत्रों की तय लागत और परिवर्तनशील लागत) को स्पष्ट रूप से अलग-अलग रखने का प्रावधान है। सुनिश्चित रिटर्न में इक्विटी पर रिटर्न का एक सुरक्षित दायरा तय किया गया है, जिसकी न्यूनतम सीमा 12 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 16 फीसदी निर्धारित की गई है।

विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए निवेश को मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, चार साल की अवधि के बाद तत्कालीन विनिमय दरों के आधार पर तय लागत को भारतीय रुपये में बदल दिया जाएगा।

अनुमान है कि इन रणनीतिक सुधारों की बदौलत पुरानी 2012 नीति की तुलना में इस नीति के तहत स्थापित होने वाले प्रत्येक नए संयंत्र से 250 करोड़ से अधिक की बचत होगी। अब से देश में सभी नए यूरिया संयंत्रों की स्थापना इस नीति के नियमों के तहत ही होगी, जो भारत को उर्वरक क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता के बेहद करीब ले जाएगी।

ट्रंप के 1 डॉलर सोने के सिक्के की तस्वीर जारी

वाशिंगटन, (हि.स.) अमेरिका को इस साल चार जुलाई को आजाद हुए 250 साल पूरे हो गए. ऐसे में अमेरिका की आजादी के 250 वर्ष पूरे होने के मौके पर अमेरिकी सरकार एक डॉलर का सोने का सिक्का शुरू करने जा रहा है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस सिक्के पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर होगी। यह अमेरिकी मूल्यों की मजबूती और सभी के लिए स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक है। यह एक तरह का स्मरणीय गोल्ड कॉइन होगा। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर है।

ब्रिटिश सिख महिला की चाकू घोंपकर हत्या

लंदन, (आरएनएन)। ब्रिटेन के लंदन में एक हमलावर ने घर के भीतर घुस कर 24 साल की एक ब्रिटिश सिख महिला की चाकू घोंप कर हत्या कर दी और 20-25 साल का एक व्यक्ति इस हमले में घायल हो गया। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि रविवार को जब अधिकारी लंदन एम्बुलेंस सेवा के साथ हेज में अक्सब्रिज रोड पर इस मकान में पहुंचे तब किरणदीप कौर घायल अवस्था में मिलीं।

आज का इतिहास

- **1661:** स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया।
- **1856:** हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली।
- **1905:** बागेरहाटर (अब बंगलादेश) में एक जनसभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दी गई।
- **1909:** भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म।
- **1925:** इराक में राजा फैसल ने बगदाद में पहली संसद स्थापित की।
- **1945:** अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया।
- **1951:** नेपाल को ब्रिटेन से आजादी मिली।

चेतावनी गूगल एआई चीफ डेमिस हसाबिस की डराने वाली चेतावनी, एआई लगातार बेहतर कर रहा...

सुपर ह्यूमन एआई आने में कुछ वक्त और, खतरे में मानवता

● वाशिंगटन / (एजेंसी)

गूगल के एआई चीफ डेमिस हसाबिस ने एआई के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एआई लगातार अपने आप को बेहतर कर रहा है। ऐसे में इन पर निगरानी रखने के लिए एक वैश्विक संस्था का बनाया जाना आवश्यक है, जो कि इनके विकास को नियंत्रित कर सके।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एक तरफ तो इंसानों को आश्चर्यचकित कर रही है। दूसरी तरफ डरा भी रही है। गूगल के एआई सेक्टर के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने भी एक ऐसी ही चेतावनी दी है, जिसको लेकर लोगों के मन में अब नया डर बैठ गया है। डेमिस का कहना है कि सुपर ह्यूमन एआई सामने आने में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है।

ऐसे में अगर जल्दी ही इसको लेकर वैश्विक नियम कायदे नहीं बनाए गए, तो यह मानवता के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर एक निगरानी संस्था बनानी होगी, जो कि एआई के निर्माण पर नजर रखे। यह कदम जल्दी ही उठाने होंगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह मानवता के

हित में नहीं होगा।

नोबेल पुरस्कार विजेता और गूगल के एआई सेक्टर के प्रमुख डेमिस हसाबिस ने अपने पर्सनल ब्लॉग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हम एआई से जुड़ी चिंताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ टेक कंपनियां लगातार इसका विकास करती जा रही हैं। अब तो एआई भी अपने से बेहतर एआई का निर्माण कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब एक सुपर ह्यूमन एआई हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, जिसे एआई विशेषज्ञ भी अपने काबू में नहीं कर पाएंगे।

एआई से लगातार बढ़ रहा जोखिम, नियम-कानून की जरूरत : हसाबिस

उन्होंने लिखा, जैसे-जैसे हम एजीआई के करीब पहुंच रहे हैं। एआई से उत्पन्न होने वाले जोखिम भी बढ़ रहे हैं। हमें इनको लेकर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि अत्याधुनिक एआई मॉडल किस तरीके से साइबर चुनौतियां पैदा करते हैं। हमें समझना होगा कि एआई की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। इससे परमाणु और बायो जोखिम भी बढ़ रहे हैं।

एआई को अब अपने मानव विशेषज्ञ की भी जरूरत नहीं

गूगल जैसे टेक कंपनी के एआई चीफ होने के नाते हसाबिस ने इस बात पर चिंता जताई है कि एआई लगातार अपने आप को बेहतर कर रहा है। इसके लिए इसे अपने मानव विशेषज्ञ की भी जरूरत नहीं है। यह आज हर दिन के साथ खुद को बेहतर कर रहा है। यह एक रोमांचित कर देने वाली घटना है लेकिन इसके साथ ही एक डर भी पैदा करती है। गौरतलब है कि एसाबिस पहले व्यक्ति नहीं हैं, जो इस तरह की चेतावनी देते आ रहे हैं। इससे पहले भी एआई के जन्मदाता जॉन मैकार्थी और वर्तमान में सबसे अत्याधुनिक एआई मॉडल बनाने वाले क्लाउड एआई भी इसी तरह की चेतावनी दे चुके हैं। क्लाउड एआई के सीईओ डारियो अमोदेई लगातार एआई से जुड़े जोखिमों के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि विशेषज्ञ भी एआई के काम करने के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं। एआई लगातार अपने आप को विकसित और बेहतर कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इन्हें लेकर एक नियम कानून बनाने की जरूरत है, ताकि इनके विकास को नियंत्रित करके मानवता के हित में किया जा सके।

पूर्वी कमान पहुंचे सेना प्रमुख, सुरक्षा स्थिति की जांच की

नई दिल्ली, (एजेंसी) । सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आस-पास के क्षेत्रों के दौरे के बाद बुधवार को रणनीतिक रूप से अहम पूर्वी कमान की प्रमुख सैन्य इकाइयों का दौरा कर संचालन तैयारियों और मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया है।इस दौरान उन्होंने सतर्कता, आधुनिकीकरण और युद्ध के लिए तैयारी पर भारतीय सेना के फोकस को फिर से दोहराया। जनरल सेठ कोपूर्वी कमान में संवेदनशील सीमाओं पर सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दी गई।

संपादकीय

सुनें तार्किक विरोध

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती रही है कि यहां हर अलग राय व असहमति को सम्मान मिला है। निश्चय ही यह दृष्टि लोकतंत्र को मजबूत ही करती है। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो प्रतिरोध की आवाज को सुनने के लिये नीति-नियंताओं को बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। एक बार फिर इस भावना की परीक्षा तब हो रही है, जब हमारे देश में लाखों बच्चों का भविष्य तय करने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे हैं। परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाये रखने के लिये शिक्षाविद् और इनोवेटर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर देश में चिंता है। उनका वजन काफी कम हुआ है, रक्त शर्करा कम हुई है और कमजोरी आने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से हटकर उनकी खराब होती सेहत हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। निश्चय ही वांगचुक किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते और न ही वे यह आंदोलन किसी निजी लाभ के लिये कर रहे हैं। वे भले ही छात्रों के भविष्य के मुद्दे को लेकर अस्तित्व में आई- कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हों, लेकिन उनकी चिंता के केंद्र में उन लाखों छात्रों का भविष्य है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के तौर-तरीकों को लेकर अविश्वास जता रहे हैं। उनके आंदोलन के मूल में उन लाखों अभिभावकों की फिक्र है, जिनका भरोसा बार-बार पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर डगमगा रहा है। कहना मुश्किल है कि लगाया जा रहा हर आरोप सही ही हो, लेकिन एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की कई महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में लोगों का विश्वास कम हुआ है। ऐसे में देश के नीति-नियंताओं को पारदर्शी सुधार लाकर और बेहतर जवाबदेही के माध्यम से दरके हुए विश्वास को जल्द बहाल करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से ये लोकतंत्र का तकाजा भी है कि सत्ताधीशों को किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन नागरिकों की बात को भी सुनना चाहिए, जो नीतियों की विसंगतियों को लेकर सवाल उठा रहे हों। यह जानते हुए कि उनकी राजनीतिक दल विशेष से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। निस्संदेह, देश में कोई भी सरकार जनता के अभिभावक के रूप में होती है। वैसे भी किसी शांतिपूर्ण विरोध की लंबे समय तक अनदेखी से आंदोलनकारियों और आम लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। निस्संदेह, यदि आंदोलनकारियों से बातचीत की पहल होती है तो इसको उसकी कमजोरी नहीं कहा जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भूख हड़ताल के नैतिक और चिकित्सीय पहलू भी होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आंदोलन कर रहे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हुए उसके जीवन की रक्षा करे। वहीं दूसरी ओर किसी भी चिकित्सीय हस्तक्षेप के दौरान कानून और चिकित्सा-संबंधी नैतिक नियमों का पालन किया जाना भी जरूरी है। इस बात में दो राय नहीं है कि मौजूदा गतिरोध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। सही मायने में बातचीत की शुरूआत करने के लिये सरकार को हर मांग को पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों को भी बातचीत को सार्थक बनाने के लिये प्रयासरत रहने की जरूरत है। ऐसे में समस्या के समाधान के लिये एक भरोसेमंद समिति और चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिये एक तय समय-सीमा वाला रोडमैप, भरोसे की कमी को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। सही मायने में इस आंदोलन के मानवीय पक्ष पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यानी सरकार समझने की कोशिश करे कि इस आंदोलन के जन्म लेने के पीछे क्या भावनाएं काम कर रही थीं।

देश में विकसित संस्कृति के विकास से बढ़ा आयकर का दायरा

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या उद्योगों की वृद्धि के साथ ही इस बात से भी होती है कि उसके नागरिक आर्थिक रूप से कितने जागरूक, जिम्मेदार और अनुशासित हैं। आज भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की लगातार बढ़ती संख्या इसी सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। निश्चित ही भारतीय जनसंख्या का यह कदम देश में विकसित होती वित्तीय संस्कृति, बढ़ती कर-अनुपालन की भावना और औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते समाज का प्रतिबिंब है।

आयकर विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल होने की जानकारी इस बदलाव का स्पष्ट प्रमाण है, जिसमेंकि एक ही दिन में 10 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह व्यवहार आर्थिक अनुशासन का परिचायक है और विकसित देशों की कर संस्कृति से मेल खाता है।

साथ ही भारत सरकार के उन प्रयासों को भी दशार्ता है, जिसमें कि भारत में पिछले एक दशक के दौरान कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल, प्री-फिल्ड रिटर्न, आधार-पैन एकीकरण, ऑनलाइन सत्यापन, फेसलेस असेसमेंट और त्वरित रिफंड जैसी व्यवस्थाओं ने करदाताओं की कठिनाइयों को काफी कम किया है। अब आईटीआर दाखिल करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। यही कारण है कि पहले जो लोग आयकर प्रक्रिया से दूरी बनाए रखते थे, वे भी अब औपचारिक कर व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। वस्तुतः आज भारत सरकार द्वारा नए आईटीआर फॉर्म में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और कुछ प्रकार के ट्रेडिंग लेनदेन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी अनिवार्य किए जाने से यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इससे कर चोरी की संभावनाएं कम होंगी और ईमानदार करदाताओं के लिए व्यवस्था अधिक विश्वसनीय बनेगी। कहना होगा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि का सीधा प्रभाव प्रत्यक्ष कर संग्रह पर भी दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की प्रारंभिक अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.64 प्रतिशत और सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12.46 प्रतिशत की वृद्धि यह बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था का औपचारिक दायरा लगातार विस्तृत हो रहा है। प्रत्यक्ष कर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे स्वस्थ राजस्व स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि वे आय और लाभ पर आधारित होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक स्थिति को भी प्रतिबिंबित करते हैं। यह परिवर्तन वस्तुतः इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय समाज में वित्तीय साक्षरता भी तेजी से बढ़ी है। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन निवेश, म्यूचुअल फंड, बीमा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पूंजी बाजार में बढ़ती भागीदारी ने नागरिकों को अपनी आय और निवेश का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित किया है। आज युवाओं के लिए आयकर रिटर्न भरना केवल कर भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी वित्तीय पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। बैंक ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण, वीजा, सरकारी निविदाओं तथा अनेक वित्तीय प्रक्रियाओं में आईटीआर की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि अनेक ऐसे लोग भी नियमित रूप से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, जिनकी कर देनदारी सीमित या शून्य है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल भुगतान प्रणाली, जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ढांचा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), औपचारिक रोजगार में वृद्धि और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भी कर आधार को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नकदी आधारित लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग से आर्थिक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण मजबूत हुआ है, जिससे कर प्रशासन अधिक प्रभावी बना है। इस बढ़त के कारण से देश का राजस्व मजबूत हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका सीधा संबंध देश के विकास से है। सरकार को जितना अधिक प्रत्यक्ष कर प्राप्त होगा, उतनी ही अधिक क्षमता उसके पास आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, रेलवे, सड़क, सिंचाई, डिजिटल नेटवर्क और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में निवेश करने की होगी। करदाता और विकास के बीच यह संबंध जितना मजबूत होगा, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति भी उतनी ही स्थायी होगी। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेज आर्थिक विकास के साथ ही जिम्मेदार नागरिक, व्यापक कर आधार और स्वैच्छिक कर अनुपालन भी आवश्यक है। इस दृष्टि से 1.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न का समय से पहले दाखिल होना आज भारत की बदलती राष्ट्रीय मानसिकता का संकेत है। यह बताता है कि भारत का नागरिक अब आर्थिक अधिकारों के साथ-साथ अपने आर्थिक दायित्वों के प्रति भी पहले से अधिक सजग हो रहा है। अब कहना यही होगा कि आयकर का बढ़ता दायरा भारत की बढ़ती आय, विस्तृत होती औपचारिक अर्थव्यवस्था, तकनीक आधारित सुशासन और आर्थिक शिक्षा के प्रसार का सम्मिलित परिणाम है। यह उस

भारतीय उच्च शिक्षा की स्वायत्तता और केंद्रीयकरण का महासंग्राम

ओ.पी. पाल

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किए गए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 ने देश के शैक्षणिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विचाराधीन यह विधेयक अपने अंतिम चरण में है और समिति आगामी मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है, जिसके साथ ही नया कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह विधेयक केवल कुछ प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आजादी के बाद से चले आ रहे उच्च शिक्षा के पूरे ढांचे को आमूल-चूल बदलने का खाका है।

दशकों पुराने नियामकों- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को समाप्त कर एक एकीकृत सुपर आयोग और उसकी तीन सहायक काउंसिलों की स्थापना का प्रस्ताव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार एक राष्ट्र, एक नियामक की नीति पर आगे बढ़ रही है। परंतु, इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ ही जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, वह है कि क्या यह सुधार भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, या यह स्वायत्तता को समाप्त कर इसे पूरी तरह से नौकरशाही और केंद्रीय नियंत्रण के पिंजरे में कैद कर देगा?

केंद्र सरकार का विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 निस्संदेह भारतीय उच्च शिक्षा के औपनिवेशिक और अप्रचलित ढांचे को बदलने का एक साहसिक प्रयास है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियामकों की भूलभुलैया को खत्म करना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस प्रक्रिया में सुधार के नाम पर स्वायत्तता की बलि चढ़ाना आत्मघाती साबित हो सकता है। इसलिए इस प्रयास में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए नियंत्रण की नहीं, बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को अपनी अंतिम रिपोर्ट में विशेष रुप से स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण को लेकर सरकार को अपीलीय शक्ति अपने हाथ में रखने के बजाय उच्च शिक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने की सिफारिश करना अनिवार्य है, जिसका नेतृत्व उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। इसी प्रकार आईआईटी और आईआईएम जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए इस कानून में एक विशेष उपबंध होना चाहिए, ताकि उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और अकादमिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

इसके अलावा फंडिंग के लिए पारदर्शी बोर्ड को लेकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे फंडिंग के बजाय एक स्वायत्त हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमेटी का गठन करना चाहिए, जो पूरी तरह गैर-राजनीतिक और अकादमिक विशेषज्ञों से सुसज्जित हो। यदि सरकार इन सुझावों को समाहित कर एक संतुलित कानून लाती है, तभी यह विधेयक सही मायनों में विकसित भारत की नींव रख पाएगा। अन्यथा, अत्यधिक केंद्रीयकरण और नौकरशाही के बोझ तले दबकर हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था अपनी बची-खुची रचनात्मकता भी खो देगी।

एक सुपर आयोग और तीन काउंसिल

इस प्रस्तावित कानून के तहत मौजूदा विखंडित नियामक व्यवस्था को समाप्त कर एक एकल महा-आयोग स्थापित किया जाएगा। इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में सामान्य उच्च शिक्षा के अलावा तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और आर्किटेक्चर शिक्षा को लाया गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार केवल चिकित्सा और कानूनी पाठ्यक्रमों को इसकी सीमा से बाहर रखा गया है।

इस महा-आयोग के सुचारु संचालन के लिए तीन विशिष्ट काउंसिलों का गठन किया जाएगा, जो कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र होंगी। इनमें रेगुलेटरी काउंसिल (नियामक परिषद), जो नए संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के लिए न्यूनतम भौतिक व शैक्षणिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और छात्रों व संस्थानों की शिकायतों के निवारण के लिए प्राथमिक निकाय होगी। दूसरी स्टैंडर्ड्स काउंसिल (मानक परिषद), जिसका मुख्य कार्य पाठ्यक्रमों के लिए लर्निंग आउटकम (सीखने के परिणाम) तय करना और अकादमिक मानकों का निर्धारण करना होगा ताकि देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में एकरूपता लाई जा सके। तीसरी वर्तमान में नैक (एनएएसी) की व्यवस्था का स्थान पर एक्रेडिटेशन काउंसिल (प्रत्यायन परिषद) होगी, जो काउंसिल संस्थानों की ग्रेडिंग, रैंकिंग और मान्यता के लिए एक नया व पारदर्शी एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगी। हालांकि प्रसिद्ध नीति विश्लेषक संस्था पीआरएस द्वारा इस विधेयक के प्रावधानों के विश्लेषण पर नजर ड़ाले, तो इस बिल के कई विरोधाभासों को रेखांकित किया गया है। खासतौर से नई शिक्षा नीति-2020 में एक ऐसे अंब्रेला रेगुलेटर का खाका खींचा गया था, जिसमें रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग और एकेडमिक मानक तय करने के लिए चार स्वतंत्र वर्टिकल होने थे।

लेकिन, इस नए बिल में फंडिंग के महत्वपूर्ण हिस्से को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। केंद्र से फंड पाने वाले संस्थानों को अब ग्रांट सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जरिए दी जाएगी, जो एनईपी के मूल ढांचे से अलग है।

वैश्विक स्तर के संस्थानों स्वायत्तता का संकट?

आईआईटी और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों पर संकट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान भारत के ऐसे मुकुट रत्न हैं जिनकी वैश्विक साख उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता के कारण है। ये संस्थान संसद के विशेष अधिनियमों के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जिन्हें अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, पाठ्यक्रम तय करने और फीस निर्धारित करने की खुली आजादी रही है। लेकिन नया विधेयक इन संस्थानों की इस विशिष्ट स्वायत्तता पर सीधा प्रहार करता प्रतीत होता है। सुपर आयोग के सीधे नियंत्रण में आना अब तक अपनी स्वायत्त शासी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संचालित होने वाले आईआईटी और आईआईएम भी सीधे इस नए आयोग के विनियामक दायरे में आ जाएंगे। यदि इन वैश्विक स्तर के संस्थानों को भी सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह एक ही लाठी से हांका गया, तो इनकी निर्णय लेने की गति धीमी हो जाएगी। वैश्विक शोध और नवाचार के लिए जिस त्वरित और लचीली प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वह नौकरशाही के जटिल नियमों में उलझकर रह जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में यूजीसी ने उच्च श्रेणी के विश्वविद्यालयों को बिना पूर्व अनुमति के देश-विदेश में 'ऑफ-कैंपस' या सैटेलाइट सेंटर खोलने की स्वतंत्रता दी थी। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना था। लेकिन इस नए विधेयक में किसी भी ऑफ-कैंपस सेंटर को खोलने के लिए रेगुलेटरी काउंसिल की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को वापस पलटने जैसा है। न्यायिक शून्यता और अपीलीय व्यवस्था में सरकार का एकाधिकार इस विधेयक का सबसे विवादित और चिंताजनक पहलू इसकी अपीलीय संरचना है। एक स्वस्थ लोकतंत्र और निष्पक्ष विनियामक व्यवस्था में चेक्स एंड बैलेंसेज (नियंत्रण और संतुलन) का होना अनिवार्य है।

विधेयक को लेकर तर्क-वितर्क

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने इस विधेयक का अध्ययन किया है और अब तक 20 से अधिक बैठकों के बाद अपनी रिपोर्ट 20 जुलाई से शुरु हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने वाली है। शिक्षाविदों और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं हैं कि यह विधेयक उच्च शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण को अत्यधिक बढ़ा देगा। इस विधेयक के समर्थकों का तर्क है कि सीधे मंत्रालय द्वारा फंडिंग से लालफीताशाही कम होगी और बजटीय आवंटन त्वरित गति से सीधे संस्थानों तक पहुंचेगा।

जबकि आलोचकों और शिक्षाविदों का मानना है कि फंडिंग का सीधे मंत्रालय के हाथ में जाना शैक्षणिक संस्थानों की रीढ़ तोड़ने जैसा है। जब कोई राजनीतिक या प्रशासनिक विंग सीधे वित्तीय कमान संभालेगा, तो अनुदानों का राजनीतिकरण होने का खतरा बढ़ जाएगा। जो संस्थान सरकार की नीतियों या विचारधारा के अनुकूल नहीं होंगे, उनकी फंडिंग को रोकना या प्रभावित करना आसान हो जाएगा। यह कदम नियामक की निष्पक्षता को भी कमजोर करता है।

क्या भारत में अनशन केवल आंदोलन है, या राजनीति की पटकथा लिखने वाला एक माध्यम?

संजय राय

भारतीय लोकतंत्र में अनशन केवल विरोध का एक साधन नहीं रहा है। यह नैतिक दबाव, जनभावना और राजनीतिक परिवर्तन का ऐसा माध्यम भी रहा है, जिसने कई बार इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन इतिहास का एक दिलचस्प पक्ष यह भी है कि अनशन करने वाले की मूल मांग और उसके परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं रहे। कई बार जो परिवर्तन सामने आया, वह आंदोलन के घोषित उद्देश्य से बिल्कुल अलग निकला।

यही कारण है कि जब भी देश में कोई बड़ा सार्वजनिक अनशन होता है, तो उसके तत्काल कारणों से अधिक उसके संभावित राजनीतिक और सामाजिक परिणामों पर चर्चा शुरू हो जाती है। क्या इतिहास स्वयं को दोहराता है? या हर बड़ा जनांदोलन अपने साथ ऐसे अप्रत्याशित बदलाव लेकर आता है, जिन्हें उस समय कोई नहीं देख पाता?

महात्मा गांधी के अनशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। गांधीजी ने अपने उपवासों का सहारा सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक एकता, अहिंसा और स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक शक्ति देने के लिए लिया। उनका उद्देश्य भारत को एकजुट रखना था। किंतु इतिहास का अंतिम परिणाम देश के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के रूप में सामने आया। यह कहना उचित नहीं होगा कि गांधीजी के अनशन से विभाजन हुआ, क्योंकि विभाजन के पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक और औपनिवेशिक कारण थे। लेकिन यह अवश्य सत्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए नैतिक संघर्षों का अंतिम राजनीतिक परिणाम गांधीजी की मूल आकांक्षाओं से भिन्न निकला।

दशकों बाद देश ने एक और ऐतिहासिक अनशन देखा। वर्ष 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन लोकपाल की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। ऐसा लगा कि अब भारत की राजनीति में जवाबदेही का नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम जन लोकपाल कानून नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी का उदय और अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख चेहरा बनना रहा। आज भी अनेक लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या उस आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था थी, या एक नई राजनीतिक शक्ति का जन्म?

यह इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, जनांदोलन हमेशा अपने घोषित उद्देश्य तक सीमित नहीं रहते। वे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, नए नेतृत्व को जन्म दे सकते हैं और सत्ता की दिशा बदल सकते हैं।

इसी संदर्भ में हाल के वर्षों में सोनम वांगचुक के आंदोलनों को भी देखा जा रहा है। उन्होंने पहले लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण, फिर संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। बाद में विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उनका संघर्ष मुख्यतः लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों पर आधारित रहा है।

अब प्रश्न यह नहीं है कि किसी एक अनशन का परिणाम क्या होगा, बल्कि यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में ऐसे आंदोलनों के दूरगामी प्रभाव तत्काल दिखाई देते हैं? इतिहास बताता है कि कई बार नहीं। कई परिवर्तन वर्षों बाद स्पष्ट होते हैं।

सोशल मीडिया के युग में एक और दिलचस्प प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे ही कोई बड़ा आंदोलन शुरू होता है, लोग तुरंत उसके पक्ष और विपक्ष में बंट जाते हैं। कुछ उसे क्रांति मान लेते हैं, तो कुछ उसे राजनीतिक साजिश घोषित कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर इन दोनों ध्रुवों के बीच कहीं होती है। किसी भी बड़े आंदोलन के पीछे सामाजिक असंतोष, राजनीतिक अवसर, मीडिया की भूमिका, जनभावना और सत्ता की प्रतिक्रिया, सभी मिलकर परिणाम तय करते हैं।

इसलिए किसी भी आंदोलन को केवल भावनाओं के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी केवल समर्थन या विरोध तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें तथ्यों, उद्देश्यों और संभावित परिणामों का भी गंभीर विश्लेषण करना चाहिए।

यह भी सच है कि भारत में आंदोलनों का राजनीतिक उपयोग और राजनीतिक प्रभाव, दोनों अलग-अलग बातें हैं। हर आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा संचालित हो, यह आवश्यक नहीं। वहीं यह भी संभव है कि किसी आंदोलन से बाद में राजनीतिक लाभ या नई राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं।

इसलिए किसी भी वर्तमान आंदोलन के बारे में यह निश्चित रूप से कहना कि उसका भविष्य क्या होगा, केवल अनुमान ही होगा। लोकतांत्रिक समाज में घटनाओं का विश्लेषण तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, न कि पूर्वधारणाओं के आधार पर। यदि भविष्य में किसी आंदोलन से नए राजनीतिक नेतृत्व, नई नीतियाँ या नए सामाजिक विमर्श जन्म लेते हैं, तो उनका मूल्यांकन उस समय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यहाँ विचारों का संघर्ष हिंसा से नहीं, बल्कि संवाद, आंदोलन और जनमत के माध्यम से होता है। अनशन उसी लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। यह नैतिक दबाव का माध्यम है, न कि अपने आप में परिवर्तन की गारंटी। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि किसी आंदोलन की सफलता केवल उसकी मूल मांग पूरी होने से नहीं मापी जाती। कई बार उसका सबसे बड़ा प्रभाव समाज की चेतना को बदलना होता है। कई बार वह नई राजनीतिक सोच को जन्म देता है। और कभी-कभी वह सत्ता तथा जनता के बीच संवाद का नया अध्याय खोल देता है। आज जब देश में विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर आंदोलन होते हैं, तब आम नागरिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भावनाओं और तथ्यों के बीच संतुलन बनाए रखना। किसी भी घटना पर तत्काल निष्कर्ष निकालना आसान है, लेकिन इतिहास अक्सर धैर्य की मांग करता है। संभव है कि आज जो केवल एक आंदोलन दिखाई दे रहा हो, वह आने वाले वर्षों में किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन का आधार बने। यह भी संभव है कि उसका प्रभाव सीमित रह जाए। दोनों संभावनाएँ लोकतंत्र में समान रूप से मौजूद हैं।

इसलिए शायद सबसे संतुलित दृष्टिकोण यही है कि हम न तो किसी आंदोलन को तुरंत ऐतिहासिक क्रांति घोषित करें और न ही उसे बिना प्रमाण किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मान लें। इतिहास का मूल्यांकन समय करता है।

अंततः भारतीय लोकतंत्र की कहानी हमें यही बताती है कि अनशन केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है; वह विचारों की शक्ति, जनविश्वास और नैतिक आग्रह का प्रतीक है। लेकिन उसके परिणाम हमेशा सीधे, सरल और पूवार्नुमेय नहीं होते। कई बार इतिहास ऐसी पटकथा लिखता है, जिसकी कल्पना स्वयं आंदोलन के नायक भी नहीं कर पाते।

शायद इसलिए, किसी भी बड़े आंदोलन को समझने के लिए सबसे आवश्यक गुण है, धैर्य। समय ही बताएगा कि आज के आंदोलनों का स्थान भविष्य के इतिहास में कहाँ निर्धारित होगा। तब तक एक सजग नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम प्रश्न पूछें, तथ्यों की जांच करें, भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखें। यही परिपक्व लोकतंत्र की पहचान भी है।

खामोश वैचारिक पदयात्रा: दीनदयाल का अंत्योदय

विवेक रंजन श्रीवास्तव

इतिहास की धूल-भरी पुस्तकों में महापुरुषों को अक्सर पत्थर की मूर्तियों की तरह दर्ज किया जाता है ठोस, अडिग और लगभग भावशून्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते ही मन मेंह्यएकात्म मानववाद की गंभीर शब्दावली उभरती है, पर उनके जीवन और चिंतन को केवल राजनीतिक सिद्धांत के रूप में पढ़ना पर्याप्त नहीं है। उन्हें समझना उस मौन दार्शनिक से संवाद करना है, जिसने शोर के युग में खामोशी को अपनी शक्ति बनाया।

हम प्रायः उनके व्यक्तित्व को राजनीति की चकाचौंध में देखते हैं, जबकि उनकी असली छाप उस सादगी में है जो उनके आचरण, दृष्टि और जीवन-शैली में झलकती थी। उनका संयम, उनका आत्मानुशासन और साधारण जन के प्रति उनकी गहरी संवेदना केवल व्यक्तिगत गुण नहीं थे; वे उनके दर्शन की जीवंत अभिव्यक्ति थे। वे उस अकिंचन दृष्टि के प्रतिनिधि थे, जिसमें सत्ता का आकर्षण नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा केंद्र में रहती है। उनके लिए अंत्योदय कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक गहरा मानवीय आग्रह था, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को गरिमा और अवसर देना।

कल्पना कीजिए उस विचारक की, जिसने सत्ता के शीर्ष पदों को नहीं भोगा, फिर भी भारतीय राजनीतिक चिंतन पर गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। उन्होंने व्यक्ति को समाज से अलग, अकेली इकाई मानने से इनकार किया। उनके लिए मनुष्य केवल आर्थिक उपभोक्ता नहीं, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वित रूप था। इसी समग्र दृष्टि से उन्होंने ह्यएकात्म मानववादह्न का प्रतिपादन किया, जिसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच गहरा अंतसंर्बंध स्वीकार किया गया। यह विचार आधुनिक युग के उस विखंडन के विरुद्ध एक शांत, पर दृढ़ प्रतिरोध था, जिसमें मनुष्य तकनीक का उपयोग करते-करते स्वयं तकनीक-निर्भर और भीतर से बिखरा हुआ होने लगता है।

आज के डिजिटल युग में हम कनेक्टिविटी को उपकरणों और मंचों से मापते हैं, जबकि संबंधों की वास्तविकता कई बार उससे दूर होती जाती है। दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन इस स्थिति को एक भिन्न दृष्टि से देखने का आग्रह करता है। यदि समाज का एक भी अंग पीड़ित है, तो सम्पूर्ण समाज स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। यह केवल राजनीतिक अर्थशास्त्र की भाषा नहीं, जीवन की जैविक और नैतिक सच्चाई है। उनका दर्शन हमें याद दिलाता है कि विकास का मूल्यांकन केवल उत्पादन, उपभोग या गति से नहीं, बल्कि मनुष्य की गरिमा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आत्मबोध से होना चाहिए।

उनकी मृत्यु ने भी भारतीय सार्वजनिक जीवन में एक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ दिया। 11 फरवरी 1968 की रात मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास उनका शव मिला, और इसके बाद उनकी मृत्यु को लेकर लंबे समय तक अनेक शंकाएँ और चचाएँ बनी रहीं। यह केवल एक व्यक्ति की असामयिक मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस विचार की भी परीक्षा थी जिसे उन्होंने जीवन भर साधा। परंतु विडंबना यह रही कि देह चली गई, विचार रह गया। शायद यही कारण है कि आज भी उनका नाम केवल एक राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक प्रेरणा के रूप में स्मरण किया जाता है।

आज जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शोर और उपभोक्तावादी स्पर्धा के बीच अपनी पहचान तलाश रहे हैं, तब दीनदयाल उपाध्याय का स्व का बोध और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने न पश्चिम का अंधानुकरण किया, न परंपरा को जड़ता में बदलने की वकालत की। उनका आग्रह था कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े बिना कोई समाज सार्थक प्रगति नहीं कर सकता। यही कारण है कि उनका विचार आज भी उन युवाओं के लिए दिशा-सूचक की तरह है जो आधुनिकता और आत्मपहचान के बीच संतुलन खोज रहे हैं।

अंततः, दीनदयाल उपाध्याय पर लिखा गया हर शब्द कुछ अधूरा-सा लगता है, क्योंकि वे ऐसी विभूति थे जिन्हें परिभाषाओं में समेटना सरल नहीं। उन्होंने समाज को आँकड़ों, नारों और सत्ता-समीकरणों से देखने के बजाय मानवीय संवेदना की दृष्टि दी। वे उन गलियों में आज भी जीवित प्रतीत होते हैं जहाँ उपेक्षा है, उन आँखों में जहाँ उम्मीद अभी शेष है, और उन चेहरों पर जहाँ गरिमा की लौ अब भी टिमटिमा रही है। वे केवल एक विचार नहीं, एक जीवंत नैतिक उपस्थिति थे। उन्हें समझने का सर्वोत्तम मार्ग यही है कि हम अंत्योदय की उस यात्रा में एक छोटा-सा कदम बढ़ाएँ, जिसके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया।

संयुक्त परिवार से एकल परिवार तक : क्या भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति खो रहा है?

कैलाश चन्द्र

संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें बच्चे केवल अपने माता-पिता के साथ नहीं, बल्कि भाई-बहनों, चचेरे-ममेरे भाई-बहनों, दादा-दादी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए जीवन जीना सीखते हैं। जब तीन-चार बच्चे एक साथ खेलते हैं, साथ बैठकर भोजन करते हैं, अपने खिलौने और वस्तुएँ बाँटते हैं, छोटे-बड़े का ध्यान रखते हैं और छोटी-छोटी बातों पर रूठते-मनाते हैं, तब उनके भीतर बिना किसी औपचारिक शिक्षा के सामाजिक जीवन के संस्कार विकसित होने लगते हैं। वे समझते हैं कि जीवन केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने का भी नाम है। परिवार उन्हें सहयोग, सहिष्णुता, त्याग, धैर्य, अनुशासन, साझेदारी और परस्पर उत्तरदायित्व का व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है। इसी वातावरण में परस्पर स्नेह, आत्मीयता, अपनापन और एक-दूसरे का सहारा बनने की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है।

मिलकर रहना, मिलकर काम करना, बाँटकर खाना और सुख-दुःख में साथ खड़ा रहना केवल नैतिक उपदेश नहीं रह जाते बल्कि दैनिक जीवन का सहज व्यवहार बन जाते हैं। यही अनुभव आगे चलकर सामाजिक समरसता, सद्भाव, सह-अस्तित्व और राष्ट्रीय एकात्मता की आधारशिला बनते हैं। इस दृष्टि से परिवार वास्तव में समाज की पहली पाठशाला है, जहाँ अच्छे नागरिक ही नहीं, संवेदनशील और उत्तरदायी मनुष्य भी तैयार होते हैं।

भारत की सभ्यता को यदि कुछ शब्दों में समझाना हो तो कहा जा सकता है कि यह केवल भूगोल, राजसत्ता या अर्थव्यवस्था से निर्मित राष्ट्र नहीं है; यह परिवार, परंपरा, संस्कार और पीढ़ियों की निरंतरता से बनी हुई जीवन-व्यवस्था है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसका परिवार रहा है। यहाँ परिवार केवल पति-पत्नी और बच्चों तक सीमित इकाई नहीं, बल्कि वह संस्था है जिसमें जीवन के मूल्य, आचरण की मयार्दा, संबंधों का अनुशासन, कर्तव्य की भावना, त्याग की परंपरा और संस्कृति की धारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होती रही है।

यही कारण है कि भारतीय परिवार व्यवस्था को केवल सामाजिक ढाँचा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत आधार माना गया है। आज यह आधार एक गंभीर संक्रमण से गुजर रहा है।

संयुक्त परिवारों का स्थान तेजी से एकल परिवार लेते जा रहे हैं। शहरीकरण, रोजगार, उपभोक्तावादी जीवन-दृष्टि, निजी स्वतंत्रता की बढ़ती आकांक्षा और बदलती जीवन-शैली ने परिवार की संरचना को बदल दिया है। यह परिवर्तन केवल रहने की व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है; यह भारतीय समाज की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक निरंतरता और पीढ़ियों के बीच जीवित संवाद पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि संयुक्त परिवार बेहतर है या एकल परिवार, बल्कि यह है कि क्या भारत अपनी परिवार-केन्द्रित सांस्कृतिक शक्ति को खोता जा रहा है? भारतीय परंपरा में संयुक्त परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं था। वह जीवन की सामूहिक साधना थी।

उसमें दादा-दादी का अनुभव, माता-पिता का परिश्रम, चाचा-चाची का सहयोग, भाई-बहनों का स्नेह और बच्चों की किलकारियाँ मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करते थे जिसमें व्यक्ति अकेला नहीं पड़ता था। जीवन की कठिनाइयाँ साझा होती थीं, सुख-दुःख का भार बँटता था, निर्णयों में अनुभव का संतुलन होता था और बच्चों को स्वाभाविक रूप से अनेक संबंधों के बीच जीना सीखने का अवसर मिलता था। संयुक्त परिवार व्यक्ति को यह सिखाता था कि जीवन केवल अधिकारों का नाम नहीं, बल्कि दायित्व, अनुशासन और सहअस्तित्व का भी नाम है। इसके विपरीत एकल परिवार आधुनिक जीवन की अनिवार्यता के रूप में सामने आया। नौकरी, स्थानांतरण, महानगरीय जीवन, सीमित संसाधन और निजी जीवन की बढ़ती चाह ने इसे सामान्य बना दिया। यह स्वीकार करना होगा कि एकल परिवार के अपने कुछ व्यावहारिक लाभ हैं।

उसमें निर्णय लेने की सुविधा होती है, निजता अधिक होती है, आर्थिक प्रबंधन सरल होता है और पारिवारिक हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम होता है। परंतु यही एकल परिवार जब भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से कट जाता है, तब वह सुविधा का ढाँचा तो बनता है, लेकिन संस्कार का केंद्र नहीं रह पाता। परिणामस्वरूप पति-पत्नी पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ता है, बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास सीमित होता है, और बुजुर्ग जीवन के सबसे संवेदनशील काल में अकेलेपन और उपेक्षा का सामना करते हैं। यहीं भारतीय परिवार व्यवस्था की सांस्कृतिक शक्ति का प्रश्न सबसे महत्त्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय परिवार की असली शक्ति उसकी संख्या या आकार में नहीं, बल्कि उसके संस्कार-तंत्र में रही है।

यह परिवार ही था जिसने बच्चे को बोलना और चलना ही नहीं, बल्कि बड़ों का सम्मान करना, छोटे का संरक्षण करना, अतिथि का आदर करना, भोजन को प्रसाद की दृष्टि से देखना, पर्व-त्योहारों के माध्यम से सामूहिकता जीना, संकट में धैर्य रखना और व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर परिवार के हित को रखना सिखाया। भारत में विद्यालय ज्ञान दे सकता है, राज्य अधिकार दे सकता है, बाजार सुविधा दे सकता है; पर चरित्र, संवेदना और सांस्कृतिक आत्मा देने का कार्य मुख्यतः परिवार ही करता है।

आईआरडीएआई के अध्यक्ष श्री अजय सेठ ने उपभोक्ता जागरूकता कॉमिक बुक सिरीज का किया अनावरण

मुंबई। बीमा सबके लिए (Insurance for All) के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के चेयरमैन श्री अजय सेठ ने उपभोक्ताओं के मध्य जीवन बीमा की अवधारणाओं को आसान बनाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपभोक्ता जागरूकता कॉमिक बुक श्रृंखला का अनावरण किया। जीवन बीमा क्षेत्र के प्रमुख लीडर्स ने एक मंच पर आकर जीवन बीमा को सारे देशवासियों और परिवारों के लिए अधिक आसान, सरल और प्रासंगिक बनाने की दिशा में अपने साझा संकल्प को मजबूत किया। यह शिक्षाप्रद कॉमिक बुक सिरीज जीवन बीमा की समझ को सरल और लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि संभावित खरीदारों के साथ वे लोग भी, जो जीवन बीमा लेने से बचते हैं, प्रायः इसे कठिन मानते हैं। इस पहल का उद्देश्य एमडब्ल्यूपी(Married Women's Property Act), वेवर ऑफ प्रीमियम (Waiver of Premium - WoP) तथा गंभीर बीमारी राइडर जैसी प्रमुख अवधारणाओं को सरलता से समझाना है। इन विशिष्ट अवधारणाओं को तकनीकी भाषा के बजाय रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सीखने के माध्यम के रूप में कॉमिक्स का चयन इस बात का संकेत है कि अब कहानी-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। यह विभिन्न आयु वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों से सहज रूप से जुड़ती है।

यह सिरीज युवा जीवन बीमा सलाहकार सुप्रिया की यात्रा पर आधारित है। इसके माध्यम से वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को स्टोरी मेमोरीज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि पहले लिए गए वित्तीय निर्णय भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यह प्रयास ₹बीमा सबके लिए' के व्यापक लक्ष्य की दिशा में एक सार्थक कदम है। यह केवल उत्पाद की केवल बीमा की पहुंच बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय परिवार की वित्तीय योजना का अभिन्न हिस्सा सुरक्षा को बनाना है। उन्होंने कहा इस मजबूत बनाने के लिए समिति की प्राथमिकताओं को भी साझा किया।

लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के महासचिव श्री आदित्य गुप्ता ने कहा

जानकारी तक सीमित न रहकर उपभोक्ताओं को समझदारी के साथ निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के अवसर पर शुरू की गई यह पहल आईआरडीएआई और जीवन बीमा उद्योग की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, जीवन सुरक्षा सॉल्यूशन की समझ को गहरा करना तथा भारतीय परिवारों में वित्तीय तैयारी की भावना को मजबूत करना है।

कॉमिक बुक श्रृंखला का अनावरण करते हुए आईएसी-लाइफ (क्अउ-छी) के अध्यक्ष श्री कमलेश राव ने कहा भारत की विकास गाथा उसके लोगों की उम्मीदों, प्रगति और दृढ़ता से आकार ले रही है। जैसे-जैसे देश अधिक समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, परिवारों की वित्तीय तैयारी को मजबूत करना दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। 'बीमा सबके लिए' का विजन एक परिवर्तनकारी यात्रा है। इसका उद्देश्य यात्रा में जीवन बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लोगों और परिवारों को वित्तीय आत्मविश्वास प्रदान करता है, उनकी आकांक्षाओं को समर्थन देता है और सुरक्षित परिवारों की मजबूत नींव तैयार करता है। आईआरडीएआई के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई यह उपभोक्ता जागरूकता कॉमिक बुक श्रृंखला इस मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुरक्षा के महत्व को एक अभिनव और सहज तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। पूरे इकोसिस्टम के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम भारत को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति और परिवार अपनी आकांक्षाओं की सुरक्षा कर सके और देश की विकास यात्रा में आत्मविश्वास के साथ भागीदारी कर सके। श्री राव ने पिछले एक वर्ष के दौरान आईएसी-लाइफ द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बीमा सबसे पहले' अभियान के दूसरे चरण की प्रगति की जानकारी दी। आने वाले वर्षों में बीमा जागरूकता और उपभोक्ता सहभागिता को और जीवन बीमा एक ऐसा वादा है, जो लोगों और परिवारों को जीवन की अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहने तथा आत्मविश्वास के साथ अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उद्योग ने अपनी पहुंच में उल्लेखनीय विस्तार किया है। लेकिन विकास के अगले चरण का उद्देश्य बीमा से जुड़ी बातचीत को और अधिक सरल, सहज तथा देशभर के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ बनाना है। यह उपभोक्ता जागरूकता कॉमिक बुक सिरीज कहानी कहने की शैली के माध्यम से लोगों को जोड़ने और उन्हें जीवन बीमा के महत्व को बेहतर ढंग से समझाने की दिशा में एक अभिनव पहल है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, आईआरडीएआई और उद्योग के सभी अग्रणी संस्थानों के साथ मिलकर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने तथा वित्तीय योजना के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में जीवन बीमा के प्रति विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीमा की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने में वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद देश के अनेक परिवार अब भी अप्रत्याशित जीवन परिस्थितियों के सामने आर्थिक रूप से असुरक्षित बने हुए हैं। उद्योग के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रोटेक्शन गैप को कम करने के लिए जीवन बीमा को अधिक व्यापक रूप से अपनाना दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस अवसर पर इंडिया आस्क्स व्हाई प्रायोरिटाइज लाइफ इंश्योरेंस? विषय पर एक विचारोत्तेजक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इसमें आईएसी के अध्यक्ष कमलेश राव, एलआईसी के प्रबंध निदेशक श्री दोराईस्वामी, पीएनबी मेटलाइफ के एमडी एवं सीईओ समीर बंसल, तथा इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ रुशभ गांधी शामिल हुए। इस चर्चा का संचालन स्वतंत्र वित्तीय पत्रकार सुश्री सोनिया शेनॉय ने किया। चर्चा में जीवन बीमा की भूमिका, वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाने, जागरूकता बढ़ाने तथा देशभर में सुरक्षा संबंधी समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस वर्ष का राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस ऐसे समय पर आया है, जब भारत का जीवन बीमा क्षेत्र लगातार गति पकड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उद्योग ने नए व्यवसाय प्रीमियम (एनबीपी) में सालाना आधार पर 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की, जबकि इस अवधि में 2.83 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी की गईं। यह जीवन बीमा समाधानों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी को दशार्ता है। हालांकि उद्योग की वृद्धि मजबूत रही है, लेकिन उद्योग जगत के नेताओं का मानना है कि बीमा की पैठ (इंश्योरेंस पेनिट्रेशन) क्षेत्र की वृद्धि और देश की आर्थिक प्रगति की गति के अनुरूप नहीं है। उनका साझा मत है कि बीमा सुरक्षा को प्रत्येक भारतीय परिवार तक पहुंचाने के लिए जागरूकता, विश्वास निर्माण और वित्तीय साक्षरता की दिशा में निरंतर एवं संगठित प्रयास अत्यंत आवश्यक होंगे।

Frigate GreenTech Energy Pvt Ltd
Frigate
SolarTech
A SOLAR POWER SOLUTION
Onsite services with trust ..
SOLAR POWER SOLUTIONS
Efficient & reliable solar solutions for a sustainable future.
ON-SITE SERVICES
Professional installation, testing, commissioning & maintenance at your site.
TRUST & RELIABILITY
Building long-term relationships through honesty, quality & support.
CLEAN ENERGY
Reduce carbon footprint and save on energy costs.
TRUST
QUALITY
PERFORMANCE
COMMITMENT
POWERING A
BRIGHTER TOMORROW
SAVE ENERGY COST
INCREASE PROPERTY VALUE
ECO FRIENDLY SOLUTION
RELIABLE SUSTAINABLE ENERGY
OUR SOLAR POWER & ENERGY SOLUTIONS
ROOFTOP SOLAR SYSTEM
Grid-tied Rooftop Solutions for Homes, Businesses & Industries.
SOLAR PLANT INSTALLATION
On-grid, Off-grid & Hybrid Solar Power Plant Solutions.
SOLAR INVERTERS
High Performance Inverters for Maximum Energy Efficiency.
SOLAR BATTERIES & ENERGY STORAGE
Reliable Energy Storage Solutions for Uninterrupted Power Supply.
SOLAR STRUCTURE & MOUNTING
Durable & Corrosion Resistant Structures for Long Life.
OPERATION & MAINTENANCE
Comprehensive AMC & Support for Optimal Performance.
EXPERT ENGINEERS
QUALITY ASSURANCE
TIMELY EXECUTION
AFTER SALES SUPPORT
CUSTOMER SATISFACTION
HIGH ROI & LONG TERM SAVINGS
FOR INQUIRY PLEASE CONTACT
+ 91- 9871700893
frigategreentech@gmail.com
C-65, 4th floor DDA Shed, Okhla Industrial Area Phase 1,
New Delhi 110020, India
CLEAN ENERGY FOR A BETTER PLANET
SMART SOLAR STRONGER FUTURE
GO SOLAR GO GREEN
SUSTAINABLE TODAY BETTER TOMORROW

अल्जाइमर मरीजों के लिए राहत की खबर, नई दवा ने धीमी की याददाश्त घटने की रफ्तार

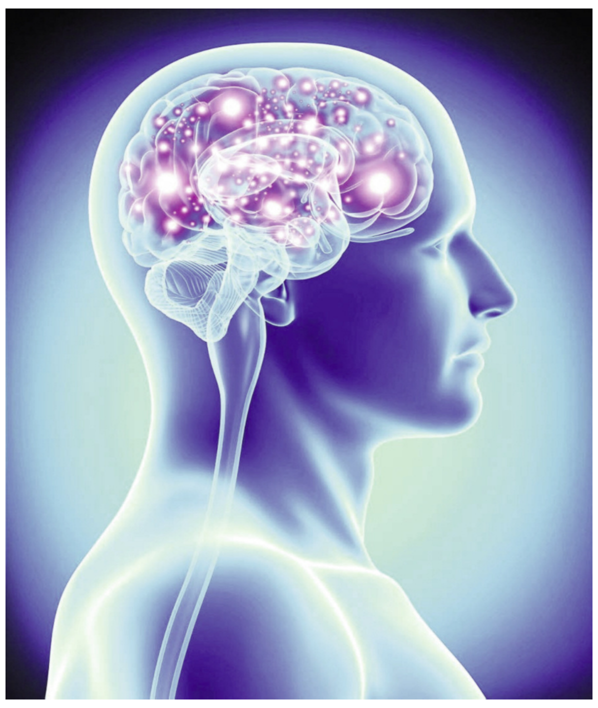

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। अल्जाइमर रोग के शुरुआती चरण से जूझ रहे मरीजों के लिए एक नए अध्ययन से उम्मीद जगी है। परीक्षणाधीन दवा डिरानर्सेन के क्लीनिकल ट्रायल में ऐसे संकेत मिले हैं कि यह दवा याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता में होने वाली गिरावट की रफ्तार को धीमा कर सकती है। साथ ही, इसने बीमारी से जुड़े खास प्रोटीन के स्तर को भी कम करने में सफलता दिखाई है।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स (यूसीएलएच) की एक न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर के अनुसार डिरानर्सेन के ट्रायल में मरीजों की सोचने-समझने और याद रखने की क्षमता में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी देखी गई। उन्होंने बताया कि दवा अभी परीक्षण के चरण में है और इसके तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल की तैयारी की जा रही है।

डिरानर्सेन का परीक्षण सीईएलआईए नामक वैश्विक अध्ययन के तहत किया गया, जिसमें शुरुआती चरण के अल्जाइमर से पीड़ित 416 मरीजों को शामिल किया गया। 18 महीने तक चले इस अध्ययन में दवा की विभिन्न खुराकोंका परीक्षण किया गया। इनमें 60 मिलीग्राम की खुराक लेने वाले मरीजों में सबसे बेहतर परिणाम देखने को मिले।

शोध के मुताबिक, 60 मिलीग्राम डोज लेने वाले मरीजों में प्लेसीबो की तुलना में बीमारी बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी रही। अलग-अलग जांचों में यह कमी 26 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक देखी गई। अल्जाइमर बीमारी में टाउ प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। यह प्रोटीन दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने और बीमारी को बढ़ाने से जुड़ा माना जाता है। डिरानर्सेन को इसी टाउ प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को कम करने के लिए तैयार किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस दवा ने मरीजों के मस्तिष्कमेरु द्रव (सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड) में मौजूद कुल टाउ प्रोटीन (टोटल टाउ) के स्तर को 50 से 65 प्रतिशत तक घटा दिया। इसके अलावा, पहली बार टाउ प्रोटीन को लक्षित करने वाली किसी दवा के परीक्षण में पीईटी स्कैन के जरिए मस्तिष्क में टाउ से जुड़े परिवर्तनों में भी कमी देखी गई।

> न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर के अनुसार डिरानर्सेन के ट्रायल में मरीजों की सोचने-समझने और याद रखने की क्षमता में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी देखी गई। उन्होंने बताया कि दवा अभी परीक्षण के चरण में है

प्रोफेसर ने कहा कि सीईएलआईए अध्ययन के परिणाम इस बात के संकेत देते हैं कि टाउ प्रोटीन के स्तर को कम करने से मरीजों को वास्तविक चिकित्सीय लाभ मिल सकता है। उनके अनुसार, डिरानर्सेन से प्राप्त परिणाम अल्जाइमर के उपचार के क्षेत्र में अब तक के सबसे उत्साहजनक निष्कर्षों में शामिल हैं और इसी आधार पर इसे बड़े स्तर के अगले चरण के परीक्षणों तक ले जाया जा रहा है। अध्ययन में दवा की सुरक्षा प्रोफाइल भी संतोषजनक रही। ज्यादातर मरीजों में साइड इफेक्ट हल्के या मध्यम स्तर के रहे। अध्ययन पूरा करने वाले 90 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों ने आगे के लंबे समय तक चलने वाले ट्रायल में शामिल होने की इच्छा जताई।

अजरबैजान में कांस्य युग की कलाकृतियों पर मिले स्वास्तिक निशान सांस्कृतिक संबंधों का संकेत

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। स्वास्तिक को दुनिया के सबसे प्राचीन और व्यापक रूप से प्रचलित पवित्र प्रतीकों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में यह शुचिता, समृद्धि, कल्याण और जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। हजारों वर्षों से इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, मंदिरों, यज्ञों और विभिन्न पर्व-त्योहारों में होता आ रहा है। भारतीय परंपरा में स्वस्तिक को मंगल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।

अब अजरबैजान से सामने आई एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक जानकारी ने इस प्राचीन प्रतीक के ऐतिहासिक महत्व को और व्यापक संदर्भ में सामने रखा है। इसकी जानकारी अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पोस्ट पर दी। वीडियो क्लिप के साथ बयान जारी किया। बताया कि अजरबैजान के शामखिर जिले के गराजामिरली क्षेत्र में कांस्य युग (ब्रॉन्ज एज) से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों पर स्वास्तिक चिह्न मिले। इन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रागैतिहासिक काल में यूरेशिया के विस्तृत भूभाग में इस प्रतीक का प्रयोग विभिन्न सभ्यताओं द्वारा किया जाता था।

> इन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रागैतिहासिक काल में यूरेशिया के विस्तृत भूभाग में इस प्रतीक का प्रयोग विभिन्न सभ्यताओं द्वारा किया जाता था

इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह की खोज केवल एक प्रतीक की उपस्थिति नहीं दर्शातीं, बल्कि यह भी बताती हैं कि प्राचीन समाजों के बीच सांस्कृतिक संपर्क, विचारों का आदान-प्रदान और साझा प्रतीकात्मक परंपराएं मौजूद थीं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि हजारों वर्ष पहले भी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध स्थापित थे।

इन साक्ष्यों ने संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए हैं। बयान के अनुसार, इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण कॉकस क्षेत्र के बीच संभावित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपर्कों पर नए सिरे से अध्ययन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे प्रतीक प्राचीन मानव सभ्यताओं की सांस्कृतिक विरासत और उनके परस्पर संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्तिक एक अत्यंत प्राचीन प्रतीक है, जिसका प्रयोग अलग-अलग सभ्यताओं में विभिन्न अर्थों और संदर्भों में हुआ है। हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता और उससे भी प्राचीन पुरातात्विक स्थलों की कई कलाकृतियों में इसका चिह्न पाया गया है। यह भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म में शुभता, सौभाग्य और कल्याण का प्रतीक है।

मनोरंजन जगत में अपनी वापसी पर बोले गोविंदा- इतनी सच्चाई से काम करूंगा कि लोग कहें, क्या यह संभव है

15 साल पहले ही साउथ इंडियन सिनेमा के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा, 'मैंने कई समय पहले ही अपने एक दोस्त से कहा था कि अगले 10 सालों में, आप साउथ इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इसके बाद साउथ सिनेमा की कई फिल्में हिट हुईं: गोविंदा

मुंबई, 15 जुलाई (एजेंसियां)। अभिनेता गोविंदा आगामी फिल्म रूपा से मनोरंजन जगत में वापसी कर रहे हैं। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिनेता ने बताया कि उन्होंने अपने काम करने के तरीके के बारे में खुलकर बात की। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने 15 साल पहले ही साउथ इंडियन सिनेमा के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा, 'मैंने कई समय पहले ही अपने एक दोस्त से कहा था कि अगले 10 सालों में, आप साउथ इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इसके बाद साउथ सिनेमा की कई फिल्में हिट हुईं। प्रभु देवा के साथ 'वांटेड', अक्षय कुमार की 'राउडी राठौर', उसके बाद अजय देवगन की 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी आई और इन सभी साउथ इंडियन फिल्मों की वजह से, हीरो लार्जर दैन लाइफ बन गए।'

अभिनेता ने बताया कि इसके पीछे की वजह ईमानदारी और अच्छा काम करना है। प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान मीडिया ने अभिनेता ने पूछा, 'क्या फिल्मों को रिलीज करने के तरीके में बदलाव आने के कारण उन्हें इंडस्ट्री में किसी तरह के विरोध या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा?'

इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेता गोविंदा ने कहा, 'मार्केट कहां है? लोग जुड़ेंगे या नहीं? लोग आएंगे या नहीं? मैं इस तरह नहीं सोचता। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता रहूंगा। इतनी सच्चाई से काम करूंगा कि लोग कहें, क्या ऐसा करना भी संभव है? तब मुझे लगेगा कि मैं गोविंदा हूं।' मीडिया ने आगे पूछा, 'क्या आप फिल्म चुनते समय किसी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू, जाने-माने डायरेक्टर या कुछ और देखते हैं?, तो इस पर अभिनेता ने कहा, 'जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय मैं सिर्फ पैसा, माता-पिता की खुशी और परिवार की खुशी देखता था। मैंने इससे ज्यादा कभी नहीं देखा।' अभिनेता ने अपनी मां की सीख को याद करते हुए कहा, 'मेरी मां ने मुझसे कहा था कि अगर तुम ये सब देखोगे, तो ऊपर वाला क्या देखेगा। बहुत से लोग ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो मुझे समझ नहीं आतीं या मैं नहीं समझता। मैं उन भाषाओं से वाकिफ नहीं हूं। कुछ लोग खतरनाक हुआ करते थे, जो हमारे जैसे गरीब परिवारों से आते हैं। वे अपनी ताकत टेस्ट करते हैं।'

12 साल की उम्र में शुरू हुआ लेखन, हिंदी रंगमंच के शिखर तक पहुंचे जगदीशचंद्र माथुर

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। यह कहानी है एक ऐसे साहित्यकार की, जिसने अपने लेखन को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की चेतना जगाने का साधन बनाया, जिनके साहित्य में ग्रामीण जीवन की सादगी, भारतीय संस्कृति की गरिमा, स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा का सशक्त स्वर सुनाई देता है। उनके जीवन के अनुभवों ने ही उनकी रचनाओं को गहराई दी। बात हो रही है हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जगदीशचंद्र माथुर की।

जगदीशचंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा के पास एक गांव में हुआ। एक छोटे से कस्बे में इनका बचपन बीता। इसी कारण ग्रामीण समस्याओं को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा। ग्रामीण जीवन से जुड़े रहने के कारण उन्होंने प्रकृति की सुंदरता, गांव के लोगों का सादा जीवन, उनकी सरलता और लोक

> ■ जगदीशचंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा के पास एक गांव में हुआ। एक छोटे से कस्बे में इनका बचपन बीता। इसी कारण ग्रामीण समस्याओं को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा

संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को नजदीक से महसूस किया। एक ललित निबंध में उन्होंने लिखा, 'सौंदर्य मेरी साधना है, किंतु पुरुषार्थ मेरी सौंदर्य साधना से भी परे लोकोत्तर सत्य है।' इन शब्दों में अनजाने ही उनका व्यक्तित्व झलकता है। जब माथुर का बचपन था, तब भारत आजाद नहीं हुआ था और देश पर अंग्रेजों का शासन था। उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। उस दौर में वह

स्कूल के छात्र थे और इन घटनाओं का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने देश की गुलामी को देखा, समझा और उसे महसूस भी किया। उनके साहित्य पर उनके माता-पिता का भी गहरा प्रभाव था। उनके पिता एक आदर्शवादी शिक्षक थे। इच्छा थी कि उनका बेटा और उनके विद्यार्थी उनसे भी अधिक योग्य और गुणवान बनें। इसलिए उन्होंने शुरू से ही माथुर की पढ़ाई और प्रतिभा पर विशेष ध्यान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि माथुर ने दूसरी या तीसरी कक्षा में ही स्कूल के कार्यक्रमों में अभिनय करना शुरू कर दिया था।

> एक ललित निबंध में उन्होंने लिखा, 'सौंदर्य मेरी साधना है, किंतु पुरुषार्थ मेरी सौंदर्य साधना से भी परे लोकोत्तर सत्य है।'

जगदीशचंद्र माथुर के जीवन पर आधारित एक लेख में इन बातों की जिक्र मिलता है।

पढ़ाई पूरी करने के बाद जब माथुर सरकारी नौकरी में आए, तब भी देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की शोषण और दमन की नीतियों से जनता परेशान थी। उन्होंने इन अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा और देशवासियों की पीड़ा को गहराई से महसूस किया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से अंधकार और निराशा में जी रही जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाओं 'भोर का तारा', 'विजय की बेला' और 'कोणार्क' में यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जगदीशचंद्र माथुर का साहित्यिक जीवन 1929 में प्रारंभ हुआ। तब उनकी आयु 12 वर्ष की थी। 1929 में 'बाल सखा' के लिए 'मुर्खेश्वर राजा' नामक प्रहसन लिखा था। इसी वर्ष उन्होंने 'लवकुश' नाटक की रचना की।

शासन और शोषण के विरूद्ध उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से आजादी की लड़ाई में अपना सहयोग दिया। सरकारी नौकरी के दौरान उन्हें यह भी महसूस हुआ कि कहीं न कहीं वे भी उस व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जो जनता पर अत्याचार कर रही थी।

'रक्तांचल 3' के प्रमोशन पर अभिनेता निकितन धीर ने बताया, 'मन का 'मैं' खत्म करना हो तो एक बार काशी जरूर आएं'

वाराणसी, 15 जुलाई (एजेंसियां)। लोकप्रिय क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'रक्तांचल' का सीजन-3 रिलीज होने के लिए तैयार है। प्रमोशन के लिए पूरी टीम वाराणसी पहुंची, जहां

> काशी की तारीफ करते हुए बताया कि यहां बहुत अच्छा काम हुआ है और समय के साथ बेहतर परिवर्तन हुआ है, गंगा मैया का पानी काफी साफ हो गया है और यहां के लोग काफी प्रोफेशनल हैं, जिससे समय के साथ काम करना बेहद आसान हो जाता है: रितम श्रीवास्तव, निर्देशक

उन्होंने बताया कि 'रक्तांचल 3' दर्शकों को पहले से ज्यादा दमदार और रोमांचक कहानी देने वाला है। निर्देशक रितम श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी सीजन में वसीम की कहानी तीसरे पड़ाव पर पहुंच गई है। यह सीजन पिछले दशक की शुरुआत की कहानी है और प्रतिस्पर्धा समय के

साथ और बढ़ती जा रही है।

उन्होंने काशी की तारीफ करते हुए बताया कि यहां बहुत अच्छा काम हुआ है और समय के साथ बेहतर परिवर्तन हुआ है, गंगा मैया का पानी काफी साफ हो गया है और यहां के लोग काफी प्रोफेशनल हैं, जिससे समय के साथ काम करना बेहद आसान हो जाता है। हमारे पास मंझे हुए एक्टर्स की टोली है। निकितन काफी कंडीशन एक्टर हैं। ये उन एक्टर्स में आते हैं, जो मेहनत करके आए और आगे अपने किरदार के लिए लगातार कर भी रहे हैं। हमारी टीम में ऐसे एक्टर शामिल हैं, जिन्हें मुझे डायरेक्शन देना नहीं पड़ता है। वहीं, निकितन धीर ने बातचीत में बताया कि एक एक्टर के तौर पर हमारे लिए यही खूबसूरती है कि हम जो भी कैरेक्टर निभाते हैं, वह अलग होता है। उन्होंने कहा, '7 साल से वसीम खान (निकितन धीर का किरदार) भी अलग-अलग रूपों में आ रहे हैं। उन्हें भी दर्शकों की तरफ से प्यार मिल रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे कैरेक्टर हमारे लिए लिखे जाएं और हम अलग-अलग रूपों में आते रहें।'

'मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए': अंजना सुखानी

बॉलीवुड के सफर का बताया अनुभव

मुंबई, 15 जुलाई (एजेंसियां)। बॉलीवुड अभिनेत्री अंजना सुखानी ने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जॉन अब्राहम और अजय देवगन जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है। अब वह अपनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर चर्चा में हैं। इस कड़ी में आईएएनएस के साथ बातचीत में अंजना ने फिल्म, इम्तियाज अली के साथ काम करने के अनुभव, फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव और अपने लंबे सफर को लेकर कई बातें साझा कीं। अंजना सुखानी ने कहा, 'मेरे लिए 'मैं वापस आऊंगा' बेहद खास फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म से इम्तियाज अली का नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। दुनियाभर के कलाकार उनके साथ काम करने का सपना देखते हैं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे यह मौका मिला। फिल्म की पूरी टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, खासकर नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ के साथ। नसीर साहब के साथ काम करना किसी लाइव मास्टरक्लास जैसा अनुभव है। उन्हें देखकर ही अभिनय की बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं।'' फिल्म में वेदांग रैना और शरवरी के साथ काम करने के अनुभव पर अंजना ने कहा, ''मेरी कहानी फिल्म में अलग समय से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके साथ ज्यादा सीन नहीं थे। हालांकि, ट्रेलर लॉन्च और शूटिंग के दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुईं। वेदांग और शरवरी दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं। जब मैंने दोनों का पहला सीन देखा तो मैं काफी प्रभावित हुई। वे फिल्म में नई ऊर्जा लेकर आए हैं।'' आज के समय में मॉडल, अभिनेता और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के बीच की दूरी कम हो रही है। इस बदलाव पर अंजना ने कहा कि अब चीजें काफी बदल गई हैं। पहले भी मॉडल फिल्मों में आते थे और अभिनेता मॉडलिंग करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी अभिनय की दुनिया में आ रहे हैं। किसी व्यक्ति में टैलेंट है और वह सच में अभिनेता बनना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए।

> 'मेरे लिए 'मैं वापस आऊंगा' बेहद खास फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म से इम्तियाज अली का नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है: अंजना सुखानी

ओडिशा: रथ तैयार, सुरक्षा कड़ी: पुरी भव्य रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार

भुवनेश्वर, 15 जुलाई (एजेंसियां)। ओडिशा का पवित्र शहर पुरी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा 16 जुलाई (गुरुवार) को 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक अपनी नौ दिवसीय वार्षिक यात्रा पर निकलेंगे।

बुधवार को वार्षिक रथ यात्रा की अंतिम तैयारियों के तहत पवित्र तटीय शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास पारंपरिक निर्माण स्थल, या 'रथ खला' से पवित्र भाई-बहनों के रथों को विधिपूर्वक स्थानांतरित किया जा रहा है।

परमानंद और धार्मिक उत्साह से ओतप्रोत होकर, दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा - क्रमश: नंदीघोष, तालध्वज और दर्पदलन के रथों को लगभग 3 किलोमीटर तक खींचकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाएंगे। पवित्र ग्रंथों के अनुसार, गुंडिचा मंदिर चतुर्धा मूर्ति (भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, माता

सुभद्रा और सुदर्शन) का जन्मस्थान माना जाता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने गुरुवार को सुचारू और बिना किसी घटना के रथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत तैयारियां की हैं।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद कुमार पाधे ने कहा कि रथ यात्रा की सभी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। उन्होंने बताया कि 'नेत्रोत्सव' और 'नव यौवन दर्शन' अनुष्ठान मंगलवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू रूप से संपन्न हुए। पाधे ने आगे बताया कि बुधवार के अनुष्ठान भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षाकर्मी गुरुवार से शुरू होने वाली रथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि पाहांडी बीजे अनुष्ठान गुरुवार को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच शुरू होगा। इससे पहले, पुरी कलेक्टर दिब्या ज्योति परिदा ने बताया कि प्रशासन ने इस वर्ष की रथ यात्रा के लिए भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक व्यवस्था की है। इस बीच, पुरी जिला पुलिस ने पुरी आने-जाने वाले वाहनों को ध्यान में रखते हुए सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए गतिशील यातायात व्यवस्था की है। पुलिस ने जनता की सुविधा के लिए 595 स्थायी और 1,050 अस्थायी साइनबोर्ड लगाए हैं।

गुंडिचा मंदिर में 'गुंडिचा मार्जन' की रस्म, श्रद्धालुओं ने की साफ-सफाई

पुरी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले बुधवार को गुंडिचा मंदिर में 'गुंडिचा मार्जन' रस्म निभाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आए और उन्होंने पूरे मंदिर परिसर की साफ-सफाई की। 'गुंडिचा मार्जन' रस्म में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के आगमन से पहले उनके अस्थायी निवास 'गुंडिचा मंदिर' की साफ-सफाई की जाती है। भगवान की 'मौसी का घर' कहे जाने वाले इस गुंडिचा मंदिर का स्वरूप प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव के दौरान दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल जाता है, जब स्वयं भगवान जगन्नाथ 7 दिनों के लिए यहां विराजमान होते हैं। हरियाणा के रोहतक से पुरी पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने कहा, 'भगवान जगन्नाथ ने मुझे 'गुंडिचा मार्जन' रस्म में शामिल होने का अवसर दिया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं।' पहली बार पुरी की रथ यात्रा का हिस्सा बनने पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। यहां का नजारा बेहद अद्भुत है। यहां की व्यवस्था भी अच्छी है।

सर्वाधिक घटने वाले शेयर

पावरग्रिड	1.73 प्रतिशत
एलएंडटी	1.69 प्रतिशत
टाटा स्टील	1.65 प्रतिशत
इंफोसिस	1.41 प्रतिशत
एनटीपीसी	1.12 प्रतिशत

सर्राफा

सोना (प्रति दस ग्राम)स्टैंडर्ड	1,42,950
बिटुर	88,730
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	39,795
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	2,20,800
वायदा	70,857
चांदी सिक्का लिवाली	900
बिकवाली	880

मुद्रा विनिमय

मुद्रा	क्रय	विक्रय
अमेरिकी डॉलर	96.85	93.78
पौंड स्टर्लिंग	130.15	125.57
यूरो	111.10	106.94
चीन युआन	15.01	13.28

अनाज

देसी गेहूँ एमपी	2400-3000
गेहूं दडा	2862.70
आटा	2800-2900
मैदा	2900-2950
चोकर	2000-2100

मोटा आनाज

बाजरा	1300-1305
मक्का	1350-1500
ज्वार	3100-3200
जौ	1430-1440
काबुली चना	3500-4000

शुगर

चीनी एस	4293.58
चीनी एम	4500-4600
मिल डिलीवरी	3620-3720
गुड़	4986.64

दाल-दलहन

चना	5700-5800
दाल चना	7798.23
मसूर काली	8109.74
उड़द दाल	10982.42
मूंग दाल	10178.50
अरहर दाल	11305.20

ओडिशा व झारखंड में दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने बुधवार को ओडिशा और झारखंड के चार जिलों को कवर करने वाली 3,907 करोड़ रुपए की लागत वाली दो मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 145 किलोमीटर का विस्तार होगा। कैबिनेट के अनुसार, इन परियोजनाओं से रेलवे लाइन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम बनेगी। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की परिचालन क्षमता और सेवा विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।

सरकार ने बताया कि प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से करीब 1,526 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जहां लगभग 14 लाख की आबादी रहती है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं से देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी। इनमें ललितगिरि बौद्ध परिसर, श्री बालदेवज्यू मंदिर और मेघाहातुबुरु हिल्स जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं।

कैबिनेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये रेल मार्ग कोयला, लौह अयस्क (आयरन ओर), डोलोमाइट, चूना पत्थर (लाइमस्टोन) और जिप्सम जैसी महत्वपूर्ण खनिज एवं औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन

■ 3,907 करोड़ रुपए की लागत वाली दो परियोजनाओं से 145 किमी बढ़ेगा रेल नेटवर्क

के लिए बेहद अहम हैं। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे की माल ढुलाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और हर साल अतिरिक्त 44 मिलियन टन (एमटीपीए) माल परिवहन संभव हो सकेगा। बयान में कहा गया कि रेलवे परिवहन पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष माध्यम है। इन परियोजनाओं से देश के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और लगभग 6 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी। साथ ही 29 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय लाभ के समान है।

सरकार ने कहा कि ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं रेलवे संचालन को अधिक सुचारु बनाएंगी और मौजूदा रेल मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कैबिनेट ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'न्यू इंडिया' के विजन के अनुरूप हैं और क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के जरिए आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी। इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इन परियोजनाओं की योजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिनका उद्देश्य एकीकृत योजना और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को मजबूत करना है।

कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 62,500 करोड़ रुपए किया स्वीकृत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) को 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी। इसके जरिए केंद्र की कोशिश मोबाइल के घरेलू उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करना है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक यानी पांच साल तक चलेगी। इसका मकसद आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना और डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) में निवेश के जरिए भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड के विकास को बढ़ावा देना है। एमपीएमस के तहत, मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बने मोबाइल फोन की योग्य बिक्री पर 2.25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की अलग-अलग दरों पर इंसेंटिव सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, यह स्कीम मुख्य पार्ट्स और सब-असेंबली की घरेलू सोर्सिंग से जुड़े 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त इंसेंटिव भी देती है। घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट डिजाइन और आरएंडडी के लिए योग्य बिक्री पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव पाने के हकदार होंगे।

डीएस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 'पल्लू प्रोटेक्शन इक्विपमेंट' जागरूकता अभियान की शुरुआत की

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। प्रमुख एफएमसीजी समूह और मल्टी-बिज़नेस कॉरपोरेशन, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप (डीएस ग्रुप) ने कृषि कार्य के दौरान कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के संपर्क से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से महिला किसानों की सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। कंपनी ने बागपत जिले के पाली, कथा, बांडपुर, सुनहेरा, बसी, मावीकला और सांकरौध सहित सात गांवों में 'पल्लू प्रोटेक्शन इक्विपमेंट' जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य केवल महिला किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करना ही नहीं, बल्कि उन्हें उनकी जरूरतों और स्थानीय जीवनशैली के अनुरूप एक व्यावहारिक सुरक्षा समाधान भी उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत जागरूकता, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा उपायों को एक साथ जोड़ते हुए सुरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीएस ग्रुप ने इस अभियान के तहत पल्लू प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) फिल्टर पेश किया है। यह धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला नैनो-फाइबर फिल्टर है, जिसे साड़ी के पल्लू या दुपट्टे में आसानी से लगाया जा सकता है। इसके बाद यही पल्लू या दुपट्टा खेती के दौरान सुरक्षा कवच का काम करता है। यह फिल्टर कीटनाशकों के महीन कणों, धूल, हानिकारक रसायनों और पीएम 2.5 जैसे प्रदूषकों से बचाव में मदद करता है। कंपनी इन फिल्टरों को बागपत के 7 गांवों में चयनित टेलर की दुकानों, कीटनाशक विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है।

मध्य पूर्व में तनाव से सोने-चांदी में कमजोरी

मुंबई, 15 जुलाई (एजेंसियां)। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब आधा प्रतिशत कम हो गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर जारी कीमतों के मुताबिक, सोने का 5 अगस्त, 2026 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,42,257 रुपए के मुकाबले 1,109 रुपए की कमजोरी के साथ 1,41,148 रुपए पर खुला।

सुबह 9:54 पर यह 607 रुपए या 0.43 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,41,650 रुपए पर था। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,40,740 रुपए का न्यूनतम स्तर और 1,41,695 रुपए का

■ कीमतें करीब आधा प्रतिशत तक लुढ़कीं

उच्चतम स्तर छुआ है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। चांदी का 4 सितंबर, 2026 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,23,189 रुपए के मुकाबले 2,21,926 रुपए पर खुला।

वित्तीय कंपनियों में तेजी से बाजार में रौनक

■ सेंसेक्स 0.17 प्रतिशत चढ़कर 77,185.43 अंक पर रहा

■ निफ्टी 0.11 प्रतिशत की बढ़त में 24,078.50 अंक पर बंद

मुंबई, 15 जुलाई (एजेंसियां)। बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों में तेजी से घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी लौट आयी और बीएसई का सेंसेक्स 130.49 अंक (0.17 प्रतिशत) चढ़कर 77,185.43 अंक पर पहुंच गया।

पिछले कारोबारी दिवस की गिरावट से उबरते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 26.45 अंक यानी 0.11 प्रतिशत की बढ़त में 24,078.50 अंक पर बंद हुआ। वृहत बाजार में

भी तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.27 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.67 प्रतिशत ऊपर रहा। बैंकिंग, वित्त, तेल एवं गैस, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, ऑटो, फार्मा, स्वास्थ्य और रसायन सेक्टरों में तेजी रही। धातु, आईटी, एफएमसीजी, मीडिया और रियल्टी समूहों के सूचकांक लुढ़क गए।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 18 से शेयर हरे निशान में रहे। इटरनल का शेयर तीन प्रतिशत की बढ़त में रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर पौने तीन प्रतिशत चढ़ा। भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडिगो, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा के शेयर एक से डेढ़ फीसदी तक मजबूत हुए। एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी पोर्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी के शेयरों में भी तेजी रही। पावरग्रिड, एलएंडटी, टाटा स्टील, इंफोसिस और एनटीपीसी के शेयर एक से पौने दो फीसदी तक टूट गए। बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनीलिवर, भारती एयरटेल, टीसीएस के शेयर भी लाल निशान में रहे।

सार संक्षेप

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव

वाशिंगटन। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वार्श ने अमेरिकी कांग्रेस में अपनी पहली पेशी के दौरान कहा कि केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फेडरल रिजर्व लगातार मूल्य स्थिरता बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है और बढ़ती महंगाई को किसी भी कीमत पर लंबे समय तक बने रहने नहीं देगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने केविन वार्श ने बताया कि जून में हुई फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में संघीय ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के दायरे में ही रखने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा, 'हमारी समिति के सदस्य लंबे समय तक ऊंची महंगाई को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।

स्कोडा ने गुजरात में खोले तीन नए बिक्री व सर्विस सेंटर

अहमदाबाद। स्कोडा ऑटो इंडिया ने गुजरात में अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए अहमदाबाद और हिम्मतनगर में तीन नये बिक्री/सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि पश्चिम भारत में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने के लिए उसने पीपीएस मोटर्स के सहयोग से ये केंद्र शुरू किए हैं। इनमें नारोडा में नया बिक्री एवं सर्विस सेंटर, मणिनगर में नया शोरूम तथा हिम्मतनगर में नया कॉम्पैक्ट 3एस (सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स) केंद्र शामिल है। अहमदाबाद के नारोडा में बिक्री एवं सर्विस सेंटर 26,700 वर्ग फुट में फैला है। इसमें छह कारों के प्रदर्शन की व्यवस्था, 19 सर्विस-बे और त्वरित रखरखाव एवं मरम्मत के लिए समर्पित स्कोडा एक्सप्रेस केयर बे उपलब्ध है। मणिनगर डीलरशिप 4,800 वर्ग फुट में है, जिसमें सात कारों के प्रदर्शन की क्षमता है।

फिक्की ने भारत-यूके सीईटीए का किया स्वागत

नई दिल्ली। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने बुधवार को भारत-यूके सीईटीए के लागू होने का स्वागत करते हुए कहा कि यह अहम समझौता भारतीय इंडस्ट्री के लिए नए मौके खोलेगा, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाएगा और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ देश की भागीदारी को मजबूत करेगा। इस समझौते के लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरुप ने कहा कि भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) से सामान और सेवाओं, दोनों ही क्षेत्रों में कारोबार के लिए नए मौके बनेंगे। स्वरुप ने कहा, 'भारत-यूके सीईटीए के लागू होने पर फिक्की की ओर से पीएम मोदी को बहुत-बहुत बधाई। यह समझौता भारतीय इंडस्ट्री के लिए सामान और सेवाओं, दोनों में नए मौके खोलेगा। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी में सहयोग से भारतीय इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।

रामायपट्टनम बंदरगाह को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के फैसले का आंध्र सरकार ने किया बचाव

अमरावती, 15 जुलाई (एजेंसियां)। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को कहा कि रामायपट्टनम बंदरगाह के संचालन और रखरखाव के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत पूरी तरह पारदर्शी बोली प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना और बंदरगाह का तेज़ी से विकास सुनिश्चित करना है।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी द्वारा गठबंधन सरकार के इस फैसले की आलोचना किए जाने के बाद राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर अपने निर्णय का बचाव किया।

सरकार ने कहा कि बोली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, जिसमें सरकार के लिए राजस्व साझेदारी, न्यूनतम गारंटीड राजस्व (एमजीआर), इक्विटी हिस्सेदारी, अग्रिम भुगतान और बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने जैसी स्पष्ट शर्तें तय की गई हैं। आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड (एपीएमबी) के माध्यम से सरकार प्रकाशम जिले में रामायपट्टनम बंदरगाह को डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल के तहत

■ वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना और बंदरगाह का तेजी से विकास सुनिश्चित करना उद्देश्य

एक प्रमुख ऑल-वेदर मल्टी-कार्गो बंदरगाह के रूप में विकसित कर रही है।

सरकार ने कहा कि बंदरगाहों के संचालन और रखरखाव में पीपीपी मॉडल कोई नई व्यवस्था नहीं है। पिछले 25-30 वर्षों से देश के प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों में इसी मॉडल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत संचालित कई बंदरगाहों में यही मॉडल अपना रही है।

सरकार के अनुसार, भारत में 119 गैर-प्रमुख बंदरगाह या तो संचालित हो रहे हैं या विकासाधीन हैं। इनमें से 108 बंदरगाह (करीब 91 प्रतिशत) पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और संचालित किए जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और पुडुचेरी जैसे राज्यों में सभी परिचालित गैर-प्रमुख बंदरगाह पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं, जबकि गुजरात के लगभग 90 प्रतिशत गैर-प्रमुख बंदरगाह भी इसी व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। सरकार ने बताया कि मौजूदा गठबंधन सरकार ने रामायपट्टनम, मछलीपट्टनम और मुलापेटा बंदरगाह परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई है। रामायपट्टनम में 80.50 प्रतिशत, मछलीपट्टनम में 58.91 प्रतिशत और मुलापेटा में 76.02 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक तीनों बंदरगाहों का निर्माण पूरा करना है।

चार चरणों (ए, बी, सी और डी) में विकसित होने वाला रामायपट्टनम बंदरगाह 2,538.42 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। पूरी परियोजना में कुल 19 बर्थ होंगे, जिनमें एक बीपीसीएल के लिए समर्पित लिक्विड बर्थ भी शामिल है।

भारत के उच्च-मूल्य मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ते कदमों के बीच, ताइवान पेश करेगा इस बदलाव को गति देने वाली अत्याधुनिक तकनीकें

मुंबई 15 जुलाई (एजेंसियां)। भारत का विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र तेजी से स्मार्ट फैक्ट्रियों और सतत (सस्टेनेबल) उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में ताइवान एक्सीलेंस ऑटोमेशन एक्सपो 2026 में ताइवान की सबसे उन्नत औद्योगिक तकनीकों का प्रदर्शन करेगा, जिससे भारतीय विनिर्माताओं को भविष्य की बुद्धिमान (इंटेलिजेंट) मैन्युफैक्चरिंग की झलक देखने का अवसर मिलेगा।

22 से 25 जुलाई तक मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित ऑटोमेशन एक्सपो 2026 में ताइवान एक्सीलेंस पवेलियन के अंतर्गत 22 पुरस्कार विजेता ताइवानी ब्रांड अपनी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें एआई एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स एवं स्मार्ट ऑटोमेशन तथा औद्योगिक उपकरण एवं कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों की अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होंगी। इनका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को उत्पादकता बढ़ाने, परिचालन क्षमता को मजबूत करने और अधिक

टिकाऊ विनिर्माण व्यवस्था विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।

इस वर्ष की भागीदारी का प्रमुख आकर्षण 22 जुलाई को आयोजित 'ताइवान एक्सीलेंस प्रोडक्ट लॉन्च' होगा, जिसकी थीम है 'ताइवान के एडैप्टिव सॉल्यूशंस के साथ सतत विनिर्माण का निर्माण'। इस अवसर पर ताइवान के चार अग्रणी ब्रांड HIWIN, IBASE, SINTRONES और SYNTEC अपनी नवीनतम औद्योगिक तकनीकों का अनावरण करेंगे। वे यह भी प्रदर्शित करेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित और एडैप्टिव तकनीकें किस प्रकार स्मार्ट एवं सतत विनिर्माण को नई दिशा दे रही हैं।

रिफाइनिंग कंपनियों का 'सुनहरा दौर' शुरू

मुंबई, 15 जुलाई (एजेंसियां)। एशिया में मौजूद रिफाइनिंग कंपनियां अपने सुनहरे दौर में प्रवेश कर रही हैं और मजबूत मांग विशेषकर डीजल से इन कंपनियों को बेहतर मार्जिन हासिल करने मदद मिलेगी। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि मार्केट भविष्य में रिफाइनिंग क्षमता में होने वाली बढ़ोतरी का अधिक अनुमान लगा रहा है, जबकि मौजूदा क्षमता में आने वाली रुकावटों को कम करके आंक रहा है। इससे आपूर्ति और मांग का संतुलन और सख्त हो जाएगा, जिससे मध्यम अवधि में रिफाइनिंग मार्जिन को सहारा मिलने का अनुमान है।

ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया कि विश्व में 23 लाख बैरल प्रति दिन से अधिक की प्रस्तावित रिफाइनिंग क्षमता में देरी या ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियां आ सकती हैं,

मजबूत मांग से होगा फायदा

जिससे प्रोडक्ट मार्केट उम्मीद से ज्यादा सख्त बने रह सकते हैं। साथ ही, उम्मीद से अधिक ईंधन की मांग खासकर डीजल की रिफाइनिंग स्प्रेड को और सहारा दे सकती है। एशियाई रिफाइनर्स का लगभग आधा रिफाइनिंग कारोबार डीजल से जुड़ा है इसलिए अगर डीजल मार्जिन ऊंचे बने रहते हैं, तो उन्हें फायदा हो सकता है। मॉर्गन स्टेनली ने भारत, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की रिफाइनरी कंपनियों को अपनी पसंद बताया है।

अब इंस्टामार्ट पर मिलेगा एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली, 15 जुलाई (एजेंसियां)। कर्नाटक में बेंगलुरु के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब यहां के गैस उपभोक्ताओं को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट के जरिए एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे।

इसके लिए इंस्टामार्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (एचपीसीएल) से हाथ मिलाया है और ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा शुरू करने की घोषणा है। गौरतलब है कि देश में पहली बार किसी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एलपीजी सिलेंडर की ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत उपभोक्ता अब इंस्टामार्ट के माध्यम से एचपीसीएल का 10 किलोग्राम 'एचपी नव्या' कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर मंगवा सकेंगे।

कंपनी ने बताया कि एचपी नव्या एक हल्का, जंग-रोधी और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर है। इसकी पारदर्शी बॉडी के कारण उपभोक्ता आसानी से गैस का स्तर देख सकते हैं। इसका ठोस डिज़ाइन इसे अपार्टमेंट, छोटे परिवारों, छात्रों,

■ जल्द शुरू होगी बेंगलुरु में ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवा

कामकाजी पेशेवरों तथा अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त बनाता है। कंपनी ने बताया कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं के पास पहले से घरेलू एलपीजी कनेक्शन होना जरूरी नहीं होगा। इससे छात्र अविवाहित कामकाजी लोग और छोटे परिवार भी आसानी से इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे। इंस्टामार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमितेश झा ने कहा कि इंस्टामार्ट अब केवल किराना सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एचपीसीएल के साथ यह साझेदारी उपभोक्ताओं को एलपीजी जैसी आवश्यक सेवा भी तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराएगी।

एचपीसीएल के निदेशक (विपणन) अमित गर्ग ने कहा कि कंपनी ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप नवाचार आधारित समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एचपी नव्या कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर के जरिए एचपीसीएल एलपीजी को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बना रहा है तथा इंस्टामार्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा। कंपनी के मुताबिक, उपभोक्ता इंस्टामार्ट ऐप पर जाकर 10 किलोग्राम एचपी नव्या कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर या पांच किलोग्राम मेटल एलपीजी सिलेंडर का चयन कर मंगवा सकते हैं।

भारतीय मतदाता संसद

भारतीय मतदाताओं का अपना संसद
जनसभा

जनसभा ही क्यों ?

जब दो बिभिन्न विचारधारा की राजनीतिक पार्टी गठबन्धन कर सरकार बना सकती हैं।
तो फिर मतदाता भी भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता ?

करके देखें ! ऐसा करने से अच्छे जनप्रतिनिधि को भी अवसर मिलेगा ! मुठितन्त्र वाली सरकार से जनप्रतिनिधि आजाद होगा ! जनप्रतिनिधि मुठितन्त्र के लिए नही लोकतंत्र के लिए होगा ! तब बदलेगा भारत

अब भारतीय मतदाता हारेगा नही, कियोंकि अपने जनसभा संसद में बैठकर अपनी और दूसरे का विचारधारा बदलेगा, फिर एक विचारधारा बनाएगा

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और जनसभा राजनीतिक व्यवस्था में अंतर

वर्तमान व्यवस्था

- किसी विशेष राजनितिक पार्टी या समर्थक के रूप में मतदाता को संगठित किया जाता है। जिस कारण मतदाता को अपना बेहतर और अनुभवी जन प्रतिनिधि के रूप में चुनने का विकल्प नही रहता इसीलिये लोकतंत्र लोकतंत्र न रहकर मुट्ठितंत्र बन जाता है।
- अधिकतर मतदाता अपना मत का अधिकार किसी विशेष पार्टी या राजनितिक के कार्यकर्ता या समर्थक के रूप में करता है जिस कारण अपने प्रतिनिधि की छवि या अनुभव महत्व नही रखता।
- भारतीय लोकतंत्र में जनता राजा है पर आज जनता नही कुछ मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं।
- मुट्ठी भर लोग राज करने से जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि का अधिकार कम हुआ।
- जनप्रतिनधि बनने के इच्छुक चुनाव के समय ही अपनी कुशलता केवल प्रचार के माध्यम से करता है। जिसमें अधिक रुपया खर्चा करना पड़ता है।
- राजनीति में धन-बल का प्रयोग ज्यादा होता है, जिससे विकास और एक समान मूल अधिकार में बाधा उत्पन होती है।

जनसभा व्यवस्था

- मतदाता मतदाता के रूप में संगठित रहेगा इसीलिये मतदाता को अपना बेहतर और अनुभवी जन प्रतिनिधि के रूप में चुनने का विकल्प रहेगा तब लोकतंत्र मुट्ठीतंत्र न बनकर लोकतंत्र रहेगा।
- अधिकतर मतदाता अपना मत का अधिकार अपने प्रतिनिधि की छवि या अनुभव के आधार पर मत का प्रयोग करेगा।
- भारतीय लोकतंत्र का जो सपना है मुट्ठी भर लोग राज नहीं आम जनता राज करे यह सपना साकार होगा।
- आम जनता का राज होने से जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि का अधिकार बढ़ेगा।
- जनप्रतिनिधि बनने के इच्छुक को अपनी कुशलता रुपया या प्रचार के माध्यम से नही जनता की अधिक समय सेवा कर दिखाने का अवसर मिलेगा।
- राजनीति में धन-बल का प्रयोग कम होगा जिससे सभी का विकास और एक समान मूल अधिकार सबको मिलेगा।

करके देखें · मुठितन्त्र से आजाद होगा हमारा जनप्रतिनिधि फिर · भारत बदलेगा

आज ही शब्दवाणी समाचार के स्थाई पाठक बनकर भारतीय मतदाता का अपना संसद जनसभा के सदस्य बनें

शब्दवाणी समाचार विज्ञापन नहीं पाठकों को प्रमुख मानता है इसलिए औरों से अलग है

आज ही शब्दवाणी समाचार (हिंदी दैनिक) के स्थाई पाठक बनें, मात्र 300 रूपये मासिक पर

सम्मान के साथ मिलेगा बहुत कुछ, लेकर देखें

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्कर करें

RNI. NO.DELHIN/2003/09049
हिन्दी दैनिक
शब्दवाणी समाचार
Website : Shabdawanisamachar.page
(नई सोच, नई उम्मीद, बेहतर भविष्य, बेहतर भारत)

अब वनडे वर्ल्ड कप में सुपर 7, टी-20 में सुपर 10 स्टेज, रोमांचक होंगे मुकाबले

प्रमुख बातें

- ☞ वनडे क्रिकेट विश्व कप में 14 टीमें ही हिस्सा लेंगी
- ☞ अब तीन चरणों में आयोजित होगा वनडे विश्वकप
- ☞ वनडे में सर्वश्रेष्ठ टीमें सुपर-7 चरण में खेलेंगी
- ☞ टी20 विश्व कप में आईपीएल की तर्ज पर एलिमिनेटर

आईसीसी ने बदला वनडे और टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट

● नई दिल्ली / (एजेंसी)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने बड़े पुरुष टूर्नामेंट- वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप के फॉर्मेट में व्यापक बदलावों को मंजूरी दी है। एडिनबर्ग में हुई आईसीसी बोर्ड की वार्षिक बैठक में मुख्य कार्यकारी समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई।

आईसीसी के मुताबिक इन बदलावों का उद्देश्य टूर्नामेंट के हर मुकाबले को अधिक प्रतिस्पर्धी, अधिक अर्थपूर्ण और ज्यादा रोमांचक बनाना है। नए प्रारूप से शुरुआती मैचों से लेकर फाइनल तक हर मुकाबले का महत्व बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा होगा और खिलाड़ियों व दर्शकों दोनों का अनुभव बेहतर बनेगा। इसके साथ ही आईसीसी ने 2028 पुरुष टी20 विश्व कप के क्वालिफिकेशन सिस्टम को भी मंजूरी दी है। वहीं, एसोसिएट सदस्य देशों के लिए 16 टीमों वाला एक नया वैश्विक टी20 टूर्नामेंट आयोजित करने के प्रस्ताव को भी बोर्ड का समर्थन मिला है। हालांकि, इस नए टूर्नामेंट को अंतिम मंजूरी नवंबर में होने वाली आईसीसी की वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति की समीक्षा के बाद मिलेगी।

सुपर-7 की चार टीमें सेमीफाइनल में खेलेंगी

सुपर-7 में पहुंचने वाली सातों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ राउंड-रॉबिन मुकाबले खेलेंगी। अंकतालिका में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके बाद पहला बनाम चौथा और दूसरा बनाम तीसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. दोनों विजेता टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। आईसीसी के मुताबिक इस प्रारूप से शुरुआती मुकाबले भी नॉकआउट जितने अहम हो जाएंगे और किसी भी टीम के लिए धीमी शुरुआत की गुंजाइश कम होगी।

तो भारत-पाकिस्तान की 3 बार होगी भिड़ंत

वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, नीमीबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में होगा और 14 टीमें शिरकत करेंगी। आईसीसी का कहना है टीमों की संख्या बढ़ाने से क्रिकेट की दुनिया में पहुंच बढ़ेगी। हालांकि, नए फॉर्मेट ने पहुंच बढ़ाने से अधिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगला विश्व कप तीन राउंड में खेला जाएगा। पहले राउंड में 12वें, 13वें और 14वें टीम एक-दूसरे का सामना करेंगी, जहां टॉप पर रहने वाली टीम अगले राउंड में जाएगी। नए फॉर्मेट को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो आईसीसी भारत और पाकिस्तान के अधिक से अधिक मैच कराना चाहती है। दोनों के बीच 3 बार भिड़ंत हो सकती है।

टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल से पहले होगा एलिमिनेटर

आईसीसी ने पुरुष टी20 विश्व कप के प्रारूप में भी बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने यह फैसला 2026 टी20 विश्व कप में उभरती टीमों के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखते हुए लिया है। आईसीसी का मानना है कि इससे दूसरे चरण में अधिक टीमों को खेलने का मौका मिलेगा और टूर्नामेंट का रोमांच अंतिम मुकाबलों तक बना रहेगा। पहले चार ग्रुप में पांच-पांच टीमें होती थीं। अब पांच ग्रुप होंगे और प्रत्येक ग्रुप में चार-चार टीमें रहेंगी। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी।

▶ **फीफा विश्व कप 2026 : ओयारजाबल और पोरो ने तोड़ा एम्बाप्पे का सपना**

फ्रांस को 2-0 से रौंदकर स्पेन 16 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में

● नई दिल्ली / (एजेंसी)

फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट मिल गया है। टेक्सास के डलास में खेले गए एक बेहद रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही स्पेन की टीम ने वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरी बार फाइनल का टिकट कटाया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में फाइनल खेला था और खिताब भी जीता था। दूसरी तरफ, फ्रांस का लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने का सपना चकनाचूर हो गया। मैच की शुरुआत से ही स्पेनिश टीम हावी नजर आई । मैच का पहला गोल 22वें मिनट में आया, जब स्पेन को पेनल्टी मिली। फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने ने बॉक्स के अंदर लामिन यमाल पर फाउल किया था। इस सुनहरे मौके को स्ट्राइकर मिकेल ओयारजाबल ने बेकार नहीं जाने दिया और शानदार गोल दागकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी।

दूसरे हाफ में भी स्पेन का दबदबा जारी रहा। 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दानी ओल्मो के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाया और स्पेन की बढ़त को दोगुना (2-0) कर दिया। हालांकि, 19 साल के लामिन यमाल ने भी एक शानदार गोल किया था, लेकिन क्लोज ऑफसाइड कॉल की वजह से उसे मान्य नहीं किया गया।

सेमीफाइनल में हार के बाद फ्रांस में भड़की हिंसा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस को सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जा रहा था। लेकिन सेमीफाइनल में स्पेन से हार के बाद टीम का सफर खत्म हो गया। किलीयन एम्बाप्पे की टीम के पास लगातार तीसरे फाइनल में जगह बनाने का मौका था। लेकिन डलास में खेले गए मुकाबले में 0-2 की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद फ्रांस के समर्थकों ने अपना आपा खो दिया और देश में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए। जगह-जगह आगजनी भी की गई। जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फ्रेंच टीम की हार के बाद देश की राजधानी में तनाव का माहौल देखा गया। गुस्साए फैंस ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, टीम के खिलाफ नारे लगाए। कई जगह आगजनी भी की गई, जिसके कारण दंगे का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए हैं। जिसमें देखा जा सकता है कि स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली 0-2 की हार से वे कितने आहत हैं।

सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे आज शाम 5 :30 बजे से

● नई दिल्ली / (एजेंसी)

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला वनडे मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना चुकी है अब उसके पास सीरीज अपने नाम करने का मौका रहेगा। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे कार्डिफ में खेला जाएगा, लेकिन इस मैच में यह देखना रोचक होगा कि भारतीय टीम प्लेइंग-11 में बदलाव करती है या नहीं। वहीं, कप्तान शुभमन गिल भी पहले मैच में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हो गए थे। ऐसे में वह गुरुवार को होने वाले मैच के लिए उपलब्ध रहते हैं या नहीं इस पर नजरें रहेंगी। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले शाम 5:00 बजे किया जाएगा। सोफिया गार्डेंस की पिच में अक्सर अच्छी उछाल और गति होती है।

संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर बरार/अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।

इंग्लैंड: जैकब बैथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग।

शुभमन गिल की चोट ने बढ़ाई चिंता

गिल ने बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे में भारत की छह विकेट से जीत में 80 रन बनाए थे, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा था। भारत उनके जल्द से जल्द फिट होने की उम्मीद कर रहा होगा। गिल को इससे पहले भी फिटनेस संबंधी समस्या के कारण मैदान छोड़ना पड़ा था।

अक्षर ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप-10 में शामिल

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन का इनाम आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में हासिल किया है। वहीं शुभमन गिल भी बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान के और करीब पहुंच गए हैं। अक्षर पटेल ने आईसीसी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाकर नौवां स्थान हासिल किया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में चार विकेट लेने के साथ 52 गेंदों में 57 रन बनाए और भारत की छह विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन के दम पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी रैंकिंग में 18 स्थान ऊपर चढ़कर 73वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में भी दो स्थान का सुधार क (एजेंसी) हुंच गए। टी20 सीरीज 0-4 से हारने के बाद भारत की वनडे टीम में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई।

चेस वर्ल्ड कप अब स्विस सिस्टम से खेला जाएगा

फॉर्मेट बदला, प्राइज मनी भी बढ़ी

● नई दिल्ली / (एजेंसी)

विश्व का सबसे बड़ा शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप अब नये फॉर्मेट में खेला जाएगा। आगामी 2027 से यह पूरी तरह बदल जाएगा और इसकी शुरुआत स्विस सिस्टम से होगी। अब शुरुआत से नॉकआउट मैच नहीं होंगे। पहले सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। उसके बाद सिर्फ टॉप-16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। इससे खिलाड़ियों को ज्यादा मैच खेलने का मौका मिलेगा। अब तक फिडे वर्ल्ड कप पूरी तरह नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाता था। ओपन वर्ग में 224 और महिला वर्ग में 128 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ओपन के खिलाड़ियों को 56-56 के 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। हर खिलाड़ी 9 राउंड खेलेगा। इसके बाद हर ग्रुप के टॉप-4 खिलाड़ी नॉकआउट के राउंड ऑफ-16 में पहुंचेंगे।

एक सप्ताह कम हो जाएगा समय

पहले वर्ल्ड कप करीब चार सप्ताह तक चलता था। कई खिलाड़ी पहले ही दो मैच हारकर बाहर हो जाते थे, जबकि कुछ खिलाड़ियों को लगभग एक महीने तक खेलना पड़ता था। फिडे का मानना है कि इतना लंबा टूर्नामेंट खिलाड़ियों और आयोजकों दोनों के लिए मुश्किल हो गया था। नए फॉर्मेट से प्रतियोगिता करीब एक सप्ताह छोटी हो जाएगी और सभी खिलाड़ियों को कम से कम 9 मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा।

हर खिलाड़ी को मिलेंगे 45 मिनट

स्विस चरण में फास्ट क्लासिकल टाइम कंट्रोल रहेगा। हर खिलाड़ी को पूरे मुकाबले के लिए 45 मिनट मिलेंगे और हर चाल पर 30 सेकंड का अतिरिक्त समय मिलेगा। स्विस चरण सिर्फ पांच दिन में पूरा होगा, जिसमें चार दिन डबल राउंड होंगे। इसके बाद राउंड ऑफ-16 से वही पुराना नॉकआउट फॉर्मेट रहेगा, जिसमें दो क्लासिकल गेम होंगे। बराबरी रहने पर रैपिड और ब्लिट्ज टाईब्रेक से विजेता तय होगा।

आयुष-उन्नति और लक्ष्य हारकर बाहर

जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन में भारत को निराशा

● नई दिल्ली / (एजेंसी)

बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में बुधवार को संघर्षपूर्ण मुकाबलों में हार गए जबकि लक्ष्य सेन को सीधे गेम में पराजय मिली। एशिया चैम्पियनशिप के उपविजेता आयुष को दूसरी वरीयता प्राप्त पूर्व विश्व चैम्पियन थाईलैंड के कुन्लावुत वितिदसर्न ने 21-19, 23-25, 21-15 से हराया।

विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज उन्नति को चीनी ताइपै की हुआंग यू सुन ने 16-21, 21-16, 21-15 से मात दी। आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप उपविजेता लक्ष्य को स्थानीय खिलाड़ी कोकी वातानाबे ने 38 मिनट में 21 -16, 21-14 से हराया।भारत के तीनों खिलाड़ी पहले दौर की बाधा भी पार नहीं कर सके जो अगले महीने दिल्ली में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप से पहले अच्छा संकेत नहीं है। भारत 17 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। अब भारत की उम्मीदें दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू और ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की मिश्रित टीम पर टिकी हैं। सिंधू का सामना पांचवीं वरीयता प्राप्त चीन की हान युइ से होगा।

(एजेंसी)

राज्य सब जूनियर व मिनी ग्रुप तैराकी की टीम घोषित

● भोपाल / खेल संवाददाता

इंदौर में 16 से 18 जुलाई तक आयोजित होने वाली 54वीं राज्य तैराकी प्रतियोगिता के लिए भोपाल टीम घोषित की गई है। तैराकों में मोलीआहुजा, आन्या वाडिया, हिमांशी लीलानी,जाग्वी सबनानी, आराध्या मेहता, तृषा विश्वकर्मा, तीशा पंथी, साक्षी चतुर्वेदी, दानिका बाथम,तेजस्विनी कौशल , मिताली निकुंभ, यूमायरा दत्ता, अवनी कौशल, कनुप्रिया शर्मा , किमाया तिवारी, चहक उनियाल, अथर्व बाथम, अर्णव चौधरी , ईशान सिंह सेंगर , तेजस बाथम, अरीज़, वेंकटेश के, ऋषभ कौशिक , ध्रुव नेगी , अर्णव कुशवाह , धवित पाठक , द्युतित सिंह, शौर्य साहू , वेदांत गुप्ता, तनिष्क अग्रवाल , कोविद गुप्ता, रियांश खुराना, वेदांत पांडे , आद्यमान रघुवंशी, अक्षत ठाकुर , लक्ष्य उनियाल शामिल हैं।

सैकिया आईसीसी की प्रशासन समीक्षा समिति के प्रमुख बने

बीसीसीआई सचिव को मिली बड़ी जिम्मेदारी

● नई दिल्ली , (एजेंसी)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव देवजीत सैकिया को बुधवार को आईसीसी की नई उप समिति प्रशासन समीक्षा समिति का प्रमुख बनाया गया जिसने क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए12.82 मिलियन डॉलर के ऋण को भी मंजूरी दे दी। सैकिया के अलावा क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर मोहम्मद मूसाजी और आईसीसी के नव नियुक्त स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर रोस रिवाज इस समिति में हैं। सैकिया नवगठित फ्रेंचाइजी लीग समिति में भी हैं जिसके अध्यक्ष बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तामिम इकबाल हैं। समिति में क्रिकेट नामीबिया के डॉक्टर रूडी वान वूरेन, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के रिचर्ड गूड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टॉड ग्रीनबर्ग भी हैं।

राज्य ट्रायथलॉन स्पर्धा नीमच में

● भोपाल / (एजेंसी)

30वीं मप्र सब जूनियर, जूनियर एक्वाथलॉन एवं सीनियर ट्रायथलॉन प्रतियोगिता नीमच में 23 से 26 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 24 जिलों के बालक, बालिकाएं ,महिला तथा पुरुष 12 इवेंट में भाग लेंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को आवास, किट, भोजन एवं लोकल ट्रांसपोर्ट की एंट्री फीस सहित समस्त सुविधा निशुल्क प्रदान की जाएगी। यह प्रतियोगिता प्रदेश के 40 तकनिकी अधिकारी संपन्न करवाएंगे। ओपी अवस्थी एवं जेपी सक्सेना तथा संघ के अध्यक्ष श्रीकांत तिवारी तथा उमाशंकर व्यास व्यवस्था देखेंगे।

अलगाव मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज महिला क्रिकेटर, पत्नी ने लगाए अवैध संबंध के आरोप

गार्डनर की समलैंगिक शादी में दरार, अफेयर की चर्चा

● नई दिल्ली / (एजेंसी)

पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन और ऑस्ट्रेलियाई टीम की उप कप्तान एश्ले गार्डनर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी और वैवाहिक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गार्डनर पर उनकी पत्नी मोनिका राइट ने अपनी ही टीम की साथी खिलाड़ी जॉर्जिया वॉल के साथ अफेयर रखने और शादी में धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। खबर है कि एश्ले और मोनिका नवंबर 2025 से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एश्ले गार्डनर और जॉर्जिया वॉल के बीच यह कथित रिश्ता पिछले साल भारत में खेले गए महिला वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुआ था। उस समय एश्ले की पत्नी मोनिका उन्हें सपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत आई थीं लेकिन वे इस कथित अफेयर से पूरी तरह अनजान थीं।

5 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं गार्डनर

एश्ले गार्डनर इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन महिला ऑलराउंडर्स में शुमार हैं। गार्डनर ने अपने अब तक के शानदार करियर में कुल 5 आईसीसी वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। इनमें साल 2018, 2020, 2023 और 2026 के महिला टी20 वर्ल्ड कप खिताब शामिल हैं साथ ही उन्होंने 2022 का वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है। इसके अलावा वे 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी मुख्य हिस्सा थीं। एश्ले गार्डनर को साल 2023 के टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था।

राजधानी (न्यू बॉम्बे)

दिन	रात
460 = 0	128 = 1
260 = 8	350 = 8

शुभांक

दिन	रात
470 = 1	237 = 2
347 = 4	357 = 5

भाग्यांक

2 3 5 7

www.kalyangame.com

म्यूजिकल लव स्टोरी में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर

फिल्म निर्माता भूषण कुमार और आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। इससे पहले दोनों 'आशिकी 2' और 'मलंग' जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब दोनों साथ में एक म्यूजिकल लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी करेंगे।

कैसा होगा आदित्य का किरदार?

आईएएनएस के अनुसार, मिलाप जावेरी और आदित्य रॉय कपूर एक म्यूजिकल लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। मिलाप जावेरी ने कहा कि आदित्य में प्यार और दर्द को पर्दे पर दिखाने का एक अनोखा टैलेंट है। इस फिल्म में उनका किरदार काफी गहरा और दमदार होगा, जिसे दर्शक बेहद पसंद करेंगे।

धमाकेदार एंटरटेनमेंट का वादा

'सत्यमेव जयते' और 'मरजावां' जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मिलाप जावेरी ने बताया कि इस आगामी म्यूजिकल ड्रामा लव स्टोरी में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन, बेहतरीन डायलॉग और रोमांस दिल को छू लेगा। बहरहाल, फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इसकी शूटिंग इसी साल 2026 के आखिर में शुरू होगी और यह फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

आदित्य रॉय कपूर का करियर

आदित्य रॉय कपूर ने एक लोकप्रिय चैनल पर एक वीडियो जॉकी के रूप में शुरू किया था। उन्होंने 2009 में फिल्मों में कदम रखा और 2019 की ब्लॉकबस्टर 'आशिकी 2' ने उन्हें रातोंरात एक रोमांटिक स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने 'यह जवानी है दीवानी' और 'मलंग' जैसी सफल फिल्मों में काम किया है। अब वह मिलाप जावेरी की म्यूजिकल लव स्टोरी में नजर आएंगे।

कृति सेनन अपने एग्स फ्रीज करवाए...

बताया क्यों उठाया यह कदम

कृति सेनन की उम्र इस वक्त 35 साल है। उनके कबीर बहिया के साथ रिलेशनशिप में होने की अटकलें भी लगती हैं। लेकिन शादी को लेकर कृति सेनन का अभी कोई प्लान नजर नहीं आता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 5 साल पहले ही अपने एग्स फ्रीज करवा लिए थे। उस वक्त एक खास वजह से उन्होंने यह फैसला लिया था।

कृति सेनन ने इस वजह से एग्स फ्रीज करवाए थे

कृति सेनन कहती हैं, 'मैं यह बात पहली बार बता रही हूं। मैंने अपने एग्स फ्रीज करवाए थे। मैंने बहुत समझदारी से यह काम उस समय किया, जब मुझे 'मिमी' फिल्म के लिए वजन बढ़ाना था। इससे शरीर में बदलाव आ रहे थे, मैं वजन बढ़ा ही रही थी। मैंने किसी से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि अगर हो सके तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात है। यह खुद को दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा तोहफा है। यह बात मेरे दिमाग में रह गई। फिर जब मुझे वजन बढ़ाने के लिए कहा गया, तो मुझे लगा कि यही सही समय है।' फिल्म 'मिमि' साल 2021 में रिलीज हुई थी यानी लगभग पांच साल पहले कृति सेनन ने अपने एग्स को फ्यूचर के लिए फ्रीज करवा दिया। बता दें कि एग फ्रीजिंग एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें महिला के एग्स (अंडे) को जमा करके फ्रीज कर दिया जाता है। जब कभी फ्यूचर में उसे मां बनना होता है तो इन एग्स के जरिए वह अपने बयोलॉजिकल बच्चे पैदा कर सकती है।

रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में हैं एक्ट्रेस

कृति सेनन बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं। दोनों कई बार साथ नजर आ चुके हैं। बीते दिनों इनके ब्रेकअप की अटकलें भी लग थीं। फिर यह कपल मुंबई के बांद्रा में डिनर डेट पर दिखाई दिया। पैपराजी से भी बचने की कोशिश कृति और कबीर ने नहीं की। एक वायरल वीडियो में दोनों मुस्कुरा रहे थे। एक ही गाड़ी में यह कपल घर की तरफ निकला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके रिश्ते में कोई दूरी नहीं आई।

कृति सेनन करियर फ्रंट पर क्या रही हैं?

कृति सेनन की कुछ दिनों पहले ही फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी हैं। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृति आने वाली फिल्म 'डॉन 3' में भी नजर आ सकती हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

'लॉकअप 2' के लिए फराह खान और रितेश देशमुख ने ली इतनी फीस

'लॉक अप' के दूसरे सीजन की शुरुआत से ही यह शो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शो के कंटेस्टेंट्स और ड्रामेटिक टिवस्ट के अलावा इस बार इसके नए होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख भी खूब चर्चा में हैं। दोनों को दर्शकों से काफी प्यार मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो को होस्ट करने के लिए ये सितारे कितनी फीस ले रहे हैं?

फराह ने चार्ज की इतनी फीस

सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान 'लॉक अप 2' को होस्ट करने के लिए हर एपिसोड के करीब 15 लाख से 25 लाख रुपये तक चार्ज कर रही हैं। हालांकि, इस रकम को लेकर अभी तक फराह खान या शो के मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रितेश देशमुख की फीस

रितेश देशमुख की फीस को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन सियासत की रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें भी लगभग उतनी ही फीस मिल रही है जितनी उन्हें 'बिग बॉस मराठी' होस्ट करने के दौरान मिली थी। बताया जा रहा है कि वह हर एपिसोड के करीब 20 लाख से 40 लाख रुपये तक चार्ज कर सकते हैं।

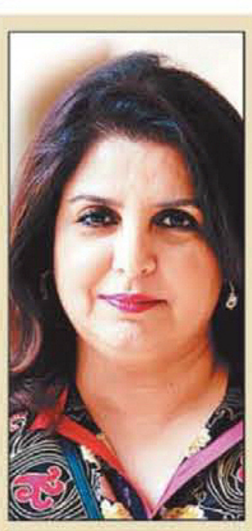

युविका से तलाक की चर्चा पर बोले प्रिंस नरूला

रियलिटी टीवी पर अपने कॉन्फिडेंट अंदाज के पीछे प्रिंस नरूला एक खामोश और कमजोर कर देने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। हाल ही में प्रिंस नरूला और उनकी पत्नी युविका चौधरी ने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें महीनों तक जबरदस्त पैनिक अटैक, रातों-रात नींद न आने और लगातार डर का सामना करना पड़ा।

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' पर बातचीत के दौरान प्रिंस नरूला ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें खुद एंग्जायटी का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के एक छोटे से गांव में पले-बढ़े होने के कारण, वहां मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं करता था। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने माना कि कई साल तक उन्हें इस बारे में गलतफहमी रही। उन्होंने स्वीकार किया कि वो ऐसे माहौल से आए थे, जहां कोई जानता भी नहीं था कि एंग्जायटी का क्या मतलब होता है। वे एंग्जायटी या डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले लोगों का मजाक उड़ाते थे और उनसे कहते थे कि बस बाहर जाओ और मजे करो। हालांकि, वो चाहते थे कि हर कोई यह समझे कि यह बिल्कुल असली चीज है।

एंग्जायटी के चलते दुनिया से बना ली दूरी

प्रिंस ने याद करते हुए कहा कि जब मुझे एंग्जायटी हुई तो मेरा दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगता था। मैं बीच ट्रैफिक में अपनी कार छोड़कर चला जाता था। दोस्तों के साथ फिल्म देखते-देखते अचानक उठकर भाग जाता था क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। मैं लगातार छह महीने तक सो नहीं पाया। मुझे अंधेरे से सचमुच डर लगने लगा था। मैंने काम करना बंद कर दिया, सबसे दूरी बना ली और दुनिया से गायब हो गया। एंग्जायटी धीरे-धीरे मेरी मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डालने लगी थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। मेरे लिवर में थकान के लक्षण दिखने लगे थे। मैं ऐसी सेहत संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था जिनका सामना मैंने पहले कभी नहीं किया था। सबसे बुरे दौर में मैं हर दिन 18 गोलियां लेता था।

मुझे सच में लगता था कि अगर मैं सो गया, तो कभी नहीं जाग पाऊंगा। इसलिए मैं सोने से बहुत डरता था और उससे बचने की पूरी कोशिश करता था। मैं अपनी बेटी के साथ हर पल बिताना चाहता था। मैंने खुद को यकीन दिला लिया था कि मुझे दुनिया की हर बीमारी हो गई है।

पृथ्वीराज सुकुमारन की 'आई, नोबडी' का टीजर रिलीज, दमदार एक्शन और सस्पेंस की झलक

अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की बहुप्रतीक्षित मलयालम फिल्म 'आई, नोबडी' का रिलीज टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म का टीजर एक्शन, सस्पेंस और दमदार संवादों से भरपूर है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का रिलीज टीजर साझा करते हुए लिखा, 'जो आने वाला है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। रिलीज टीजर अब आउट हो चुका है। अपने टिकट अभी बुक करें। 9 जुलाई से दुनियाभर के सिनेमाघरों में।' टीजर की शुरुआत एक वॉयसओवर से होती है, जिसमें राजीवन नाम के किरदार को 'फूड चेन' का उदाहरण देकर समाज की वास्तविकता समझाई जाती है। संवाद में कहा जाता है कि टिड्डा घास खाता है, उसे मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप और सांप को चील। लेकिन समाज में जीवित रहने के लिए सिर्फ घास खाना काफी नहीं, बल्कि टिड्डे को मेंढक को भी खाना सीखना होगा। आखिर में कहा जाता है कि यह फैसला आपको करना होगा कि आपको किसका सिर निगलना है।

इस वॉयसओवर के साथ फिल्म के कई तेज-तर्रार एक्शन दृश्य दिखाए गए हैं। टीजर के अंत में पुलिस पृथ्वीराज के दरवाजे पर पहुंचती है और उनसे पूछती है कि वह उनके फोन कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से यू/ए सर्टिफिकेट मिल चुका है। यह फिल्म 9 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म का शुभारंभ पिछले वर्ष अप्रैल में केरल के एर्नाकुलम स्थित वेलिंगटन आइलैंड में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुआ था। निर्देशक निसाम बशीर की इस फिल्म की कहानी और पटकथा समीर अब्दुल ने लिखी है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ पार्वती तिरुवोथु और हकीम शहजहान भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

फिल्म का निर्माण सुप्रिया मेनन, मुकेश मेहता और सी. वी. सारथी ने पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और ई4 एक्सपेरिमेंट्स के बैनर तले किया है। निर्माताओं के करीबी सूत्रों के अनुसार, 'आई, नोबडी' एक ऐसी सिनेमाई प्रस्तुति होगी, जिसमें रोमांच, भावनाएं और दमदार अभिनय का शानदार मेल देखने को मिलेगा।

मैं प्यार के मामले में बहुत बदकिस्मत हूं

टेलीविजन अभिनेत्री आकांक्षा चमोला पिछले कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनेता गौरव खन्ना के साथ करीब नौ साल पुराना रिश्ता टूटने की खबर ने उनके फैंस को पहले ही हैरान कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे खुलासे किए, जिनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। अब एक बार फिर आकांक्षा ने अपने दिल की बात साझा करते हुए कहा है कि वह प्यार के मामले में खुद को बदकिस्मत मानती हैं। आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने अब इस स'चाई को स्वीकार भी कर लिया है। नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के एक एपिसोड के दौरान आकांक्षा चमोला अपनी करीबी दोस्त पामेला सेरेना और को-कंटेस्टेंट वरुण यादव (उर्फ लैला) के साथ प्यार और रिश्तों पर खुलकर बात करती नजर आईं। बातचीत के दौरान आकांक्षा ने कहा, 'मेरी एक महिला दोस्त ने मुझसे कहा था कि दुर्भाग्य से मैं प्यार के मामले में बदकिस्मत हूं और हमेशा रहूंगी। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद यही सच है और अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

उनकी यह बात सुनकर वरुण यादव ने उनसे दोबारा पूछा, 'क्या तुम सच में प्यार के मामले में बदकिस्मत हो?' इस पर आकांक्षा ने जवाब दिया, 'हां, मैं प्यार के मामले में बहुत बदकिस्मत हूं।'

गौरतलब है कि 'लॉक अप: सच या सजा' के लॉन्च के दौरान ही आकांक्षा चमोला ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वह और उनके पति गौरव खन्ना पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और अब दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। आकांक्षा के इस बयान ने शो की होस्ट फराह खान के साथ-साथ उनके फैंस को भी चौंका दिया था। आकांक्षा और गौरव खन्ना ने नवंबर 2016 में लव मैरिज की थी। दोनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती थी। शादी के बाद दोनों करीब नौ साल तक साथ रहे, लेकिन हाल ही में आकांक्षा ने अपने सेपरेशन की पुष्टि कर दी। इसके बाद से उनकी निजी जिंदगी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।

यही नहीं, पिछले हफ्ते शो के 'जजमेंट डे' एपिसोड में भी आकांक्षा ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक और अहम खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वह बाइसेक्शुअल हैं और गौरव खन्ना से शादी करने से पहले महिलाओं के साथ भी रिश्तों में रह चुकी हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी थी और कई लोगों ने उनके साहस की सराहना भी की। इन दिनों 'लॉक अप: सच या सजा' को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं। इसमें आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज अली और वरुण यादव उर्फ लैला जैसे कई चर्चित कलाकार भी हैं।

लाला अमरनाथ पर शाहरुख संग फिल्म बनाना चाहते थे हिरानी

आमिर खान अपनी अगली फिल्म 'ललकार' में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज लाला अमरनाथ की भूमिका निभाने जा रहे हैं। इसी बीच फिल्म ब आमिर इस कहानी को 'ललकार' के रूप में बड़े परदे पर लेकर आ रहे हैं। फिल्म में उनकी जोड़ी एक बार फिर निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के साथ बनेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, 'ललकार' की कहानी 1से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर से पहले इसी विषय पर शाहरुख खान और निर्देशक राजकुमार हिरानी साथ काम करने की प्लानिंग बना चुके थे। बताया जा रहा है कि 2018 में 'जीरो' और 'संजू' की रिलीज के बाद राजकुमार हिरानी ने शाहरुख को लाला अमरनाथ की बायोपिक का आइडिया सुनाया था। हालांकि, कई कारणों से यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में कोविड-19 महामारी के दौरान प्लानिंग्स बदल गई और हिरानी ने शाहरुख को 'डंकी' का ऑफर दिया, जो 2023 में रिलीज हुई।

मोहम्मद जोशी के लिय टाइम्स मास कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पंजीकृत कार्यालय जे 85 सीमापुरी, दिल्ली से प्रकाशित इंकलाब भारत प्रेस जे एण्ड के दिलशाद गार्डन दिल्ली से मुद्रित संपादकीय कार्यालय समाचार भवन एफ-126 शाहिद नगर, चिकम्बरपुर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201006 ईमेल : shabdwanisamchaarw2003gmail.com www. shabdawanisamachar.page संपादक मोहम्मद जोशी ,सलाहकार संपादक : अशोक लालवानी

refresh™
MATTRESS
SLEEP HEALTHY. Wake beautiful.
HDFC BANK
We understand your world
Mega Exchange Offer
Limited time only
Zero Down Payment &
EMI Available on Selected Models
• Get Value upto ₹12000/- for Old Mattress
• Assured Gifts upto ₹12448/-
• Total Exchange Benifits ₹24448/-
BLOSSOM
refresh
Premium
PRISTINE
PRISTINE
PRISTINE
PRISTINE
Offer available on
1pc of 72" x 60" or 2pcs of 72" x 30"
and above
Hurry !!! Rush to your nearest dealer
Customer care no. : 18001209630